the shortage of wagons to transport coconuts in proper time. These are usually booked from Salem Station. Coconut is a perishable commodity. So, the growers will have to take the coconuts within a particular time and transport it in time. This is the season for the growers and the merchants who are engaged in coconut business. If they do not get the wagons to transport coconuts in this busy time, their business will definitely be affected greatly. Several thousands of acres in Salem, Coimbatore, Tiruchi and Dharmapuri districts are under production of coconuts. The growers of coconuts are not able to get fair prices due to the shortage and stoppage of supply of wagons. To redress these difficulties the Railway Minister may instruct the Southern Railway to restore the supply of wagons to transport coconuts in proper time.

(vii) RESTORATION OF PASSENGER/GOODS TRAINS SERVICES ON NIDAMANGALAM-MANNARGUDI RAILWAY LINES.

SHRI S. SINGARAVADIVEL (Thunjavur): The Nidamangalam Railway Junction in the Southern Railway system, is on the Thanjavur-Nagore Railway Line in my parliamentary constituency of Thanjavur. From Nidamangalam junction to Mannargudi, an important town in the Thanjavur District, there is a Branch Railway line for the last several decades covering a distance of about 12 KM and on the said lines passengers and goods trains were operated. It is the only Railway line from Mannargudi and it has no other Rail link. While so the passengers and goods trains which catered to the needs of the public for a long period on the said lines have been suspended and the public who used the services are put to great inconvenience and hardship. Travelling people from and to Mannargudi have been deprived of the rail services and they are unable to avail of the Thanjavur Nagore Railway services also.

Mannargudi, a Municipal town, is the headquarter of a taluk and has several educational institutions including an Arts College, a Govt. inpatient hospital, several temples attracting pilgrims from other places, several important Govt. offices, courts, banks, a fertiliser plant called the Pamini Fertiliser and Central Warehousing godowns among others. Number of people visit Mannargudi daily from other places and *vice-versa*. Because of the suspension of the passengers and goods services on the said line, public suffer a lot and they have to resort to roadways for their journey and transport of goods. Pamini Fertiliser and the central warehousing godowns also have to take to the road transport incurring heavy expenses. The loadmen who were engaged in loading and unloading at Mannargudi are without employment and their families suffer a lot. Only the immediate restoration of the passengers and goods trains on the Nidamangalam-Mannargudi Railway lines will solve the pressing problems of the public.

Hence, the hon. Railway Minister may be pleased to take steps for the restoration of the train service and restore the goods as well as the passengers trains on Nidamangalam-Mannargudi Railway lines immediately.

13.09 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1980-81—contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Reconstruction.

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश के देहातों में, गांवों में बसने वाली 75 फीसदी आबादी का ताल्लुक है, जिसके जीवन का दारोमदार इसी खेती पर है, काश्तकारी पर है। चाहे वह हल चलाने

[श्री मलिक एम० एम० ए० खा]

वाला काश्तकार हो, चाहे वह खेत मे काम करने वाला मजदूर हो सभी का ताल्लुक इस से है।

आम तौर से, मान्यवर, देखा गया है कि चाहे कितनी ही महगाई बढे, कास्ट आफ लिविंग चाहे कितना हो बढ़ जाये, प्राइस इन्डेक्स चाहे कितना ही बढ जाये और उसके बढने पर चाहे दफ्तरो मे काम करने वाले हो या कारखानो मे काम करने वाले हों, सभी प्राइस इन्डेक्स के बढने पर शोर मचाते हैं। कभी वे पेन डाउन स्ट्राइक, कभी वे टूल डाउन स्ट्राइक करते है। अपनी मागो का मनवाने के लिये मुख्तलिफ तरीको से दबाव पर जोर डाला जाता है। यहा एक ऐसा सैक्टर है जिस का कोई जोर नही है। अभी तक मुल्क मे पेन डाउन स्ट्राइक देखी है, टूल डाउन स्ट्राइक का देखा है लेकिन हैल्ड डाउन स्ट्राइक को अभी तक नही देखा है। यही एक सैक्टर है जो अनआर्गेनाइज्ड है, जिस की तरफ सरकार की कभी तवज्जह नही जाती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट मे लोग बैठे हुए हैं। उनमें ऐसे भी बहुत से लोग है जिन्होने आज तक गावो की शक्ल तक नही देखी है। रूरल इकोनेमी के एक्सपोर्ट यहा पर मौजूद है। मुझे एक वाकया याद आता है। एक रूरल इकानोमी के एक्सपर्ट लदन गये। उन से पूछा गया कि आप कहा के रहने वाले है। उन्होंने कहा कि मै गॉव का रहने वाला हू। जब उन से पूछा गया कि कब से आप गाव मे तशरीफ नही ले गये है तो उन्होने कहा कि सतरह साल से। सतरह साल मे जिस आदमी ने गाव की शक्ल नही देखी है वह रूरल इकोनोमी के एक्सपर्ट है। डैस्क पर बैठ कर हिसाब लगाने वालो ने कभी कोशिश की है गावों मे जा कर हालत मालूम करने की? किसान की आज हालत क्या है, उसको जानने की क्या उन्होने कभी कोशिश की है?

एक एग्रिकल्चरल प्राईसिंग कमिशन बना हुआ है। वह प्राइसिज मुकर्रर करता है। बडा महत्वपूर्ण यह कमीशन है। यहा पर ब्याइट एलीफैंट का जिक्र किया गया है। कोई रेलवे बोर्ड की सफेद हाथी कहता है और कोई किसी दूसरे को। लेकिन यह फूड डिपार्टमैंट यानी एफ० सी० आई० भी सफेद हाथी से कम नही है, ऐसा तो मै नही कहूगा इसलिये कि यह जिस खयाल से कायम किया गया था वह बहुत फायदेमन्द आर्गेनाइजेशन के रूप से किया गया था। लेकिन आज वह हमारे लिये सफेद हाथी बन गया है। इसका भी मै साबित करना चाहता हू।

शुरूआत कहां से होती है? जहा से हमारे खेत में हमारी मेहनत का खून पसीने से बहाई गई मेहनत का, साल भर की मेहनत का फल मिलने का सवाल आता है, वही से इसकी शुरूआत होती है। जब हमारे पैदावार का मूल्य देने का सवाल पैदा होता है, वहां से इसकी शुरूआत होती है। एफ सी आई जगह-जगह सेंटर खोलता पैदावार की खरीद करने के लिये। जब इसको कायम किया गया था तब यह कहा गया था कि मिडिलमैन को बीच में से निकालने के लिये इसको कायम किया जा रहा है। हाउस में भी जब जब पूछा गया है यही कहा गया है कि यह कोई प्राफिट मेकिंग आर्गेनाइजेशन नही है, लेकिन आप देखे कि इसको जब कायम किया गया था तो इसका क्या एम बताया गया था। मै एफ सी आई के रिकार्ड से ही कोट करूंगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट से ही कोट करूंगा। 20 नवम्बर, 1964 को जब इसके बारे मे बिल हाउस मे पेश किया गया था तब उस मे यह कहा गया था

"The agency will also be used to build up gradually bufferstocks and that Corporation will be encouraged to function generally as an autonomous organisation working on commercial lines."

आज हालत यह है कि यह सफेद हाथी सैकडो करोडो रुपया टैक्स पेअर का खा गया है। मै जो आकडे दूंगा वे एफ सी आई की एनुअल रिपोर्ट से ही दूगा। लेकिन उससे पहले जो खरीद का इसका तरीका है वह मै बताना चाहूगा। एफ सी आई खरीद करने के लिये सेंटर खोलता है, सूबो के लोग भी खरीद करने के लिये खोलते है और कोआपरेटिव सैक्टर मे भी खरीद की जाती है। एफ सी आई वालो ने एक टैकनीकल चीज लगा दी है और वह यह है कि क्वालिटी के हिसाब से कीमत दी जायेगी और ग्रेड 1, 2 और 3 होगे। अब क्वालिटी के हिसाब मे लेने का जहा तक सवाल है इससे कोई इन्कार नही कर सकता है लेकिन यहा तो करप्शन का दरवाजा ही इन्होने खोल दिया है। इन्सपैक्टर को होने इजाजत दे दी कि जितना वह चाहे किसान का खून चूस क्वालिटी के नाम पर। आप गेहूं साफ करा कर ले, बिल्कुल क्लीअर करवा कर ले छनवा कर ले लेकिन एक कीमत पर ले। दो दो और तीन तीन कीमते जब आप मुकर्रर करते है इससे दिक्कत पैदा होती है। दो दो और तीन तीन दिन तक किसान गाडियो को लाइन मे लगा कर खडा रहता है। धूप तेज होती है, मई जून का महीना होता है और वह लाइन में खडा रहता है; कभी उसको कह दिया जाता है कि बोरे नही है बोरे लेने के लिये साहब गये है और कभी कोई और बहाना लगा दिया जाता है; नतीजा यह होता है कि तग आ कर जो बनिया बैठा होता है, लाला बैठा होता है जो उसका एजेंट होता है, वह उसको थोडे दामों में खरीद लेता है। आप यकीन जानिये पूरे मुल्क में शायद ही एक, दो परसैंट ऐसा किसान होगा जिसको 100 रुपये पर क्विंटल से ज्यादा कीमत मिली हो और वह कीमत भी मिली या नही मिली, मै आंकडों से साबित करूंगा। कीमत एनाउन्स 110 पये की गई और एफ० सी० आई० से 102 रुपये एक्कुअल की मत काश्तकार के पास पहुंची। 1977-78 में वैल्यू पर क्विंटल 119.74 है और प्रोक्यो-

मैंट इंमोईन्टर 17.62 है और काश्तकार को क्या मिला है 102 रुपये 12 पैसे। यह आपके फूड कारपोरेशन के रिपोर्ट में आंकड़े हैं। 1977-78 में जब कि 110 रुपये कीमत एनाउन्स को सरकार ने तो काश्तकार को 102 रुपये 12 पैसे एवरेज कीमत मिली। 7.88 रुपये कम पहुंची। वहां जो कुछ मार काट होता है, वह अलग जो फूड कारपोरेशन, सरकार की जेब से पैसा गया वह 77-78 में 102 रुपये 12 पैसे गया। हमें इस आर्गेनाइजेशन के बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा। आप यकीन जानिये, इस साल 600 करोड़ रुपये सब्सीडी के दिये गये हैं।

बड़े मंत्री जो भी आ गये हैं। मैं कोई बुराई से नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि इस आर्गेनाइजेशन को संभाला जाये, यह टैक्स पेयर का सारा पैसा खा जाते हैं और बिला वजह। मैं निवेदन करूंगा कि सब्सीडी का यह आलम है :—

1973-74 में 264.2 करोड़ रुपये, 1974-75 में 264.81 करोड़ रुपये 1975-76 में 291.62 करोड़ रुपये, 1976-77 में 451.99 करोड़ रुपये, 1977-78 में 565.67 करोड़ रुपये और 1978-79 में यह 570 करोड़ रुपये और अब 1979-80 में 600 करोड़ रुपये की सब्सीडी दी गई है?

जा गेहूं और अनाज खरीदते हैं, जो मैंने हिसाब लगाया है 1 क्विंटल पर आपका 95 रुपये खर्च आता है। हम 102 रुपये पर गेहूं खरीदते हैं, बाजार में 130 रुपये बेचा जाता है। 130 पर बेचने के बाद इनको तो करोड़ों रुपये की सब्सीडी भी जाये, मगर वह लाला जी बाजार में गेहूं उसी भाव में खरीदता है और उसी भाव में बेचता है, वह कोठी बनाये खड़ा है मिल खुल रहे हैं, और तुम्हारा पैसा जो जाता है उससे ये 102 रुपये पर खरीदकर 130 रुपये पर बेच रहे हैं। आपने 1977-78 में 110 रुपये प्राइस एनाउन्स किया और 102 रुपये आपके फूड कारपोरेशन के आंकड़े से है।

28 रुपये तो मार्जिन आपको वह मिल गया और 600 करोड़ रुपये सब्सीडी मिल गया और 2 हजार करोड़ रुपये ये बैंक से लोन लेते है। लोन जो और लोगों को मिलता है, उससे 4 परसेंट कम ब्याज पर इनको लोन मिलता है और इस 4 परसेंट से यह 97 करोड़ रुपये बैठता है। यानी 28 का मारजिन, 600 करोड़ सब्सीडी और 97 करोड़ रूपये का यह फायदा सूद में। अगर हिसाब लगाएं तो एक क्विंटल पर 95 रुपये खर्च बैठता है और यह जाता कहा है? 1968 में इन्टर्नल प्रोक्युरमेंट हुआ 6.81 मिलियन टन, इमपोर्ट किया 5.7 मिलियन टन और कुल इस्यू हुआ 10.2 मिलियन टन। इस तरह साल भर में वाल्यूम आफ विजिनेस था 22.71 मिलियन टन। उस वक्त एम्पलाई थे 15,228 फूड कारपोरेशन में। मैं हर साल के फिगर्ज दे कर सदन का वक्त खराब नहीं करूंगा, बल्कि आखिर में 1978 पर आऊंगा। 1978 में वाल्युम आफ विजिनेस था 17.30 मिलियन टन और एम्पलाईज थे 67,283 आप देखें कि जब वाल्युम आफ विजिनेस 22.71 मिलियन टन था, तब एम्पलाईज 15,228 थे, और जब वाल्युम आफ विजिनेस 17.30 मिलियनटन है तो एम्पलाईज बढ़कर 67,283 हो गये। इस तरह फूड कारपोरेशन में टैक्स-पेयर के रुपये के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पर रिश्तेदारों की परवरिश हो रही है, सबसिडी ले कर पैसा बर्बाद हो रहा है और मुख्तलिफ बहाने किये जाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं यह किताब "स्टेट इन फूडग्रेन ट्रेड इन इंडिया" को सदन के टेबल पर रख दूंगा। शायद इससे मंत्री महोदय को फायदा हो जाये।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : मैं माननीय सदस्य से ले कर पढ़ लूंगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : इससे आपको अन्दाजा हो जायेगा कि यह रुपया कहां जा रहा है।

यहां पर मिडलमैन की बात कही गई है। जब फूड कारपोरेशन नही था, तो मिलडमेन का इतना बड़ा रोल नहीं था, जितना कि आज है। यह बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट चाहे 117 रुपये का भाव डिक्लेयर करे और चाहे 115 रूपये का, काश्तकार को आज तक 100 रुपये या 102 रुपये से ज्यादा नही मिला है। कुछ वहा खा जाते हैं और कुछ क्वालिटी इन्स्पेक्टर खा जाते हैं। यह जो ग्रेड वन, टू और थी का ग्रेडेशन किया जाता है, यह करप्शन की जड़ है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को कहा जाये कि वे गेहूं को छांट कर साफ कर के दें, लेकिन ग्रेडेशन नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह करप्शन और बेईमानी की जड़ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अब की बार पूरा मिला है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : कभी भी नहीं मिला है। मैं किसान हूं, गांव का रहने वाला हूं कभी भी किसान को पूरा पैसा नहीं मिला है। बीच में लाला और इंस्पेक्टर खाते है। अगर मंत्री महोदय चाहेंगे, तो मैं उन्हें साथ ले जा कर ऐसे मामले पकड़वा दूंगा।

फूड कार्पोरेशन में एक और बीमारी है ट्रांजिट और स्टोरेज लासिज। यह बड़ी भारी प्लेग है। मैं फूड कार्पोरेशन का चार साल तक डायरेक्टर

[श्री मलिक एम० एम० ए० खां]

रहा हूं। ट्रांजिट एंड स्टोरेज लासिज के बारे में एक कमेटी मुकर्रर हुई और मैं उसका चेयरमन मुकर्रर हुआ हमारे सामन फूट कारपोरेशन के आफिसर्ज हमने उनसे निवेदन किया कि इन लासिज को वाइफकेट कर दीजिये—ट्रांजिट में कितना लास होता है और गोडाउन में कितना लास होता है। एक साल उन्होंने हमें घुमाया—बड़ी डिफीकल्टी है, कैसे वाइफकट होगा, कई तरह के टेकनिकल जवाब दिये गये। मैं भी नहीं माना, कहा कि यह करना पड़ेगा। रोज बोर्ड की मीटिंग में पूछा जाता था कि क्यों देर हो रही है। हमने कहा कि ये लोग साथ नहीं देते है। आखिर यह एक्सपेरिमेंट कराया। मैं उस किताब से क्वाट करता हूं। मैं ये बाते किसी की बुराई करने की गरज से नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि काम में इम्प्रूवमेंट हो। मंत्री महोदय खुद काश्तकार है। मैं चाहता हू कि वह काश्तकारों के गले कटने से बचायें और हैवी हैंड,ज से इन गलत प्रेक्टिसिज को रोके। मैं इस किताब से पढ़ कर क्वोट करता हु। इस कमेटी का मै चेयरमैन था :

"The Committee on 'Transit and Storage Losses' carried out actual studies on movement of foodgrans between various railway stations such as Jind to Delhi-Kishan Gunj and Bejwa to Borivilli (Bombay). The Committee found that in spite of the stitchings having given way and huge spillage on wagon floor, the foodgrains actually received showed gains."

मेरे बाद एक और इसके चेयरमैन हुए। कम्प्रडा चाहे उनका आप देख ले। मैने एक बात नोट की है। मै भी किसान हू। मुझे यह बता दे कि बैशाख मे जो गेहू कटेगा उसको बरसात मे निकाले तो शार्टेज हो कैसे जायेगी? उसमे तो म्वायश्चर बढेगा। मई जून के काटे हुए गेहू मे शार्टेज कहा से हो जायेगी? ये चोरी करते है। गेहू की बोरी मे परकी लगा कर गेहू निकाल लेते हैं और बताते हैं कि लास है। मैं जानता हू, मुझे प्रैक्टिकल मालूम है। मैं चैलेंज करता हू दुनिया की कोई ताकत यह दिखा दे कि उस मे शार्टेज हो जायगी। गेहूं खरीदन के बाद और गोडाउन में लान के बाद बरसात मे निकालना जायगा तो दो से चार परसेंट तक एक्सेस जरूर होगा। मैं इसका चेयरमैन रहा हूं और मैं एक्सपेरिमेंट कराया है। उसकी रिपोर्ट मौजूद है, उसे देख लीजिए। मेरे बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई उस की रिपोर्ट सुन लीजिए। यह जो पंजाब और हरयाने का गेहूं नार्थ ईस्टर्न रीजन में जाता है उसके मुताल्लिक कहा जाता है कि उस में 6 परसेंट शार्टेज और लास है। उस के लिए एक हाई पावर कमेटी फिर उन्होंने मुकर्रर की। वह लिखते हैं :

"Another high-powered committee of the FCI is understood to have probed into the very high percentage (upto 6 per cent) of transit losses reported in the stocks despatched from Punjab/Haryana to centres in the eastern region. The investigations of this Committee are understood to have shown that there were no losses in transit in these movements. On the other hand, the grains moved through rail from Punjab to eastern regions showed some gains when weighed at the receiving stations."

हुजूरआला, गोर फरमाइये कि यह 6 परसेंट जो शार्टेज दिखाते रहे यह कहा गया? इसे कौन खाता रहा? मैं तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूं। गद्दी तो आप के हाथ म है। तो यह क्या हो रहा है फूड कापोरेशन में? एक जाल है बहुत बड़ा।

साढे सात सौ करोड एडिबल आयल इम्पोर्ट होता है। मै इस कमटी का भी चेयरमन रहा हूं आप ताज्जुब करेंगे कि जिस राइस ब्रेन म 16 से 25 परसेंट आयल है वह हमारे यहां गधे और घोड़े खाते हैं। वह जो चावल के ऊपर का हिस्सा होता है जिसे राइस ब्रैन बोलते है उस में 16 से 25 परसेंट तेल है। यह भी हम ने एक्सपरिमट कर के देखा है और राइस ब्रेन आयल कमटी की यह रिपोर्ट है कि जहां हम माडर्न मिल लगाते हैं वहा उस के साथ साथ एक्सट्रेक्शन प्लाट भी लगना चाहिये। मेरी ड्यूटी थी सलाह देने की, वह मै ने दे दी। मै मन्त्री जी से पूछना चाहूगा कि उस पर क्या कार्यवाही हुई है? जब से वह रिपोर्ट दी गई है, '73 या '74 म तब से अब तक कितने एक्सट्रक्शन प्लाट लगे है? उस रिपोर्ट मे यह दिया है कि माडन मिल के साथ साथ साइड बाइ साइड एक्सटक्शन प्लाट लगने चाहिये। आज भी हम साढे सात सौ करोड़ का एडिवल आयल इम्पपोर्ट कर रहे है। हमारे यहां गधे और घोड़े उस राईस ब्रेन को खान जाते हैं या उस घुर पर फेक देते हैं जिसमें तेल मौजूद है और जिसको हम इस्तमाल कर सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो राइस ब्रैन आयल कमेटी की रिपोर्ट है उस पर क्या कार्यवाही हुई? कितन एक्सट्रेक्शन प्लांट मुल्क के अंदर लगे हैं ताकि साढे सात सौ करोड़ के इम्पोर्ट से हम बच सकें।

कहने को तो बहुत मामले है लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं उन को अर्ज कर सकूं।

आज अभी अभी 377 के जरिये से माडर्न बेकरीज का जिक्र किया गया है। मुझे गर्व रहा है इस से भी ताल्लुक रखने का। चार साल सेवा की है। मैं एक बात पूछूंगा कि '74-75' में इस आर्गेनाइजेशन का 1 करोड़ 3 लाख का प्राफिट था, एक करोड़ तीन लाख का प्राफिट 1972-73 में था जबकि तीन लाख की रकम आउटस्टैंडिंग थी, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो एक करोड़ 6 लाख का प्राफिट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी किसी मिनिस्ट्री ने आज तक जानने की कोशिश की कि आज उसकी पर्फामन्स क्या है। मुझे माफ करें, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता लेकिन मिनिस्ट्री के कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके पब्लिक अण्डरटेकिंज को अपना अड्डा कुछ लोगों न बना लिया है। मुझे बड़ा दुःख होता है, मैं क्या अर्ज करूं, जहां मैंने सेवा की है उस को जब डबते देखता हूं तो परेशान जरूर होता हूं। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि 377 में से 103 वर्कर्स को निकाल दिया गया। मुझे मालूम है 50 सीनियर एक्सपीरियंस्ड आफिसर्स में से 20 को शण्ट कर दिया गया और उनकी जगह मैनेजमेन्ट ट्रेनी रख दिए गए हैं।

फूड कारपोरेशन ने फरीदाबाद में एक मेज क्रशिंग मिल लगाई थी। श्री इकबाल सिंह फूड कारपोरेशन के चेयरमैन थे। तब भी मैंने कहा था कि आप सफेद हाथी बांध रहे है, फरीदाबाद में जो मेज मिलिंग फैक्टरी आप लगा रहे हैं उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। उस वक्त भी हमने यह कहा था लेकिन आपने लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि वह फैक्टरी जितने दिन फूड कारपोरेशन के पास रही, उसकी क्या पर्फामेन्स है, वह कितने दिन चली, कितना प्राफिट और लास हुआ, कितने आदमी उसमें रखे गये, कितनी मेज क्रश की गई? मैं पूछना चाहता हूं कि इस मिल को एक ऐसी अण्डरटेकिंग माडर्न बेकरीज, जोकि मुनाफा दे रही थी---मैंने बताया कि एक करोड़ 6 लाख का मुनाफा दिया था---के पास क्यों ट्रान्सफर कर दिया गया? सिर्फ अपने ऐब छिपाने के लिये। फिर वहां से तरक्कियां होती है, चेयरमैन, फूड सेक्रेटरी और फलां फलां को लाओ। उनकी तरक्की होती है। मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी मेज मिल को एक ऐसी अण्डरटेकिंग के पास देने की जोकि अच्छी चल रही थी, प्राफिट दे रही थी, और आपने वर्कर्स को 20 परसेंट बोनस दे रही थी? मेरी बात को आप नोट कर लें, यह जो यूनिट्स आपने ट्रांसफर की हैं वह माडर्न बेकरीज को खा जायेंगी। मैं यह तजुर्बे की बात बता रहा हूं।

इसी तरह से मैं पूछना चाहूंगा आपने उज्जैन आयल मिल क्यों ट्रांसफर कर दी? क्या यह सही है कि एक करोड़ की मूंगफली वहां खरीदी गई थी। उस मूंगफली का क्या हुआ? क्या यह सही नहीं है कि उज्जैन आयल मिल जबसे कायम हुई है उसकी एनुअल रिपोर्ट नहीं आई? पिछले तीन सालों से उसकी कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है सब पोल-खाता चल रहा है, खाओ, पियो मस्त रहो। आप मुझे बतायें कि दो साल से उज्जैन यूनिट का क्या पंफार्मेन्स है। जो मूंगफली खरीदी गई थी क्या उसको क्रश किया गया और जो तेल निकाला गया क्या उसको मार्केट में बेचा गया और कितने में बेचा गया? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि और मूंगफली में उलटफेर हुआ है, वह क्रश नहीं हुई है। आप इसकी जानकारी करें मैं बहुत गम्भीर बात बता रहा हूं। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि मेज मिल जब से माडर्न बेकरीज के पास आई है तब से इतने दिनों में कितनी मेज का क्रशिंग हुआ, कितना फायदा और नुकसान हुआ। इसी तरह से उज्जैन मिल को कितना नुकसान और नफा हुआ है। इसी इतनी बड़ी आर्गेनाईजेशन जो 600 करोड़ की सब्सीडी दी जाती है उसको 50 करोड़ की सब्सीडी और सही लेकिन माडर्न बेकरीज का बेड़ा आप क्यों गर्क कर रहे हैं। यह तो एक प्राफिट की यूनिट थी। बेकरी के अलावा 40 लाख रु० एडवर्टिजमेंट पर खर्च हो गया, जबकि 10-12 लाख रु० रखा गया था, आखिर इसमें भी कुछ नार्मसमुकर्रर होंगे कि यह रुपया कैसे खर्च होगा। वाटलर्स कम्पनी की तरफ से मुकर्रर किये जाते हैं। उनका एलोकेशन है लेकिन कहीं अखबारों में, रेडियो में एडवर्टिजमेंट नहीं। अगर अखबारों में और रेडियो में एडवर्टिजमेंट होगा तो उसका बिल बनेगा कि इतना रुपया खर्च हुआ।

मैं स्पेसिफिक चार्ज लगा रहा हूं, आप जरा गौर फरमायें, क्या जो माडर्न बेकरीज में वाटलर्स के नार्मस मुकर्रर किये जाते है, क्या उन नार्मस के मुताबिक रुपया खर्च होता है। क्या यह सही नहीं है कि वाटलर्स मैनेजमेंट के नार्मज के खिलाफ उसी वाटलिंग फैक्ट्री में जिसमें "77" वाटलिंग होता है, उसमें अपना-अपना वाटलिंग कर रहे है खिलाफे एग्रीमेंट, खिलाफे नार्मज। यह बड़ा भारी जाल है। मेरी मंत्री महोदय से दरख्वास्त है कि यह ट्रान्सफर जो माडर्न फैक्ट्री को हुआ है, इसमें धोखाधड़ी है, इसको जरा गौर करें और इसकी जांच करायें तो पता यह माडर्न बेकरी जो है यह बिल्कुल बैठ जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट से डिमाण्ड करूंगा कि यह जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इस में देश की 75 फीसदी आबादी लगी हुई है, चाहे हल चलाने वाला हो, चाहे खेत में मजदूरी करने वाला हो। मैं चाहता हूं कि इस मद में एलोकेशन आफ फण्ड्स को और बढ़ाया जाये। आप मुझे माफ करेंगे इस बात को कहने के लिये कि लैंड डवेलपमेंट बैंक द्वारा जो किसानों को लोन दिया जाता है, वह किसानों के लिये एक प्रकार से मौत है। अगर एक दफा उन्होंने उनसे पैसा ले लिया, उनके हाथ में फस गया तो उसकी जमीन नीलाम हो गई। मेरी आप से अर्ज है कि आप इसके प्रोसीजर को भी देखें। होता क्या है कि किसान जो पम्पिंग सैट्स या इंजन लेते हैं उसके लिये भी एजेन्ट्स मुकर्रर है, उनके अलावा वह काश्तकार किसी दूसरे से नहीं ले सकता है। चैक भी उन्हीं के नाम से

[श्री मलिक एम० एम० ए० खां]

इंजन का कट जायेगा, लेकिन रिमेंनिग पैसा, जो कि पम्प खरीदने के बाद बचता है, वह भी उनको नहीं मिलना है। यह बड़ी भारी बीमारी जो काश्तकारों को तबाह कर रही है।

दूसरी बात, जो बिजली की फिक्सड् प्राइसेस हैं। उसकी भी हालत को आप जरा देखिये पूरे, साल भर किसानों को बिजली नही मिलती है, लेकिन जो रेट बिजली का 12-12.5 रुपये हार्स पावर का मुकर्रर है, वह उनसे मंथली चार्ज कर लिया जाता है। यह कितना बड़ा जुल्म है। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक मीटर लगा दो, उसके हिसाब से जितना पैसा बनता है, वह हमसे ले लो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। पानी नही, बिजली नहीं देश में सूखा है अगर इसका चार्ज किसानों पर लगाया जा रहा है और कहा जाता है कि खेत में गल्ला नहीं होगा तो घर नीलाम कर दिया जायेगा। एक तरफ तो आपने कुकर, टी० वी० और टूथपैस्ट पर रेट कम कर दिया है और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर आपने 30 रु० मंहगा कर दिया। यह आप क्या करने जा रहे है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आइंदा आप जो प्राइस फिक्स करगे, क्या उसमें आप 30 रु० क्वीटल गेहू का दाम बढायेगे ताकि फर्टिलाइजर की बढोतरी पूरी हो सके।

यह क्या तमाशा है कि सारा बजट बनाने वाले, सारा प्लानिग करने वाले जो अधिकारी है, वे सब प्लान शहरों के लिये करते है, और गांवों को तबाह कर रहे हैं यह इसलिये करते है क्योंकि गांवों में किसान यूनाइटेड सैक्टर में नही है। ये अधिकारी लोग तो डण्डे की जबान समझते है, हड़ताल की जुबान समझते है किन्तु भले आदमी की जुबान नही समझते है। यदि किसान भी आर्गेनाइज्ड हो जाये तो ये शहरों में रहने वाले, एयर कंडीशन्ड म रहन वाले सब भूखे मर जायेगे। मै यह कहना चाहता हू कि हम एयरकंडीशन्ड नहीं चाहते है, हम कूलर नहीं चाहते है, हम रोटी चाहते है और अपने बच्चों के लिये कपडा चाहते है। किसान के जरूरत की हर चीज मंहगी हो जाती है, लेकिन किसान तो पैदा करता है, अपने खून पसीने से, उसके द्वारा पैदा की हुई चीज सब सस्ती कर दी जाती है उसकी पैदा की हुई चीज को जो शक्ल चलने वाला है वह तो तीन तीन मंजिली कोठियों में रहता है लकिन पैदा करने वाला किसान झोपडियों में रहता है यह बडे अफसोस की बात है। इस चीज को आपको आज नही तो कल बदलना पडेगा और जरूर बदलना पडेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will make an announcement. There are thirtythree members from the ruling party. The time left is only 2½ hours. Therefore, I would make an appeal to all the hon. Members from the ruling party that they do not take more than five minutes each.

Mr. A. C. Das.

*SHRI A. C. DAS (Jaipur): Mr. ten minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You make a request to the Minister for Parliamentary Affairs if you want more time.

SHRI A. C. DAS (Jaipur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Rural Reconstruction. In being a mainly agricultural country agriculture occupies a very important place in our national economy. We depend upon agriculture for our food. A fertile soil can give us more crops. Good seeds, fertilizers and the modern agricultural equipments are very necessary to improve our agriculture. There are no two opinions about it. About 80 per cent of the total population of our country depend upon agriculture. The farmers live in the villages. They are below the poverty line, and they work in the fields from down to dusk and supply food to the whole of the country. They are the backbone of the nation. They are leading very miserable lives. It is our first and foremost duty to improve their lot. The development of the nation is quite impossible if the farmers are not helped and agriculture does not develop.

I am happy that the Planning Commission has taken a decision to give top priority to increasing the production of oil seeds. The Government is also taking steps to bring down the

*The original speech was delivered in Oriya.

prices. Cultivation of oilseeds, pulses, fodder and grass should be encouraged. Our country will become self-sufficient only if we increase agricultural production.

Sir, our Government is giving top priority for the upliftment of the rural areas. There is a separate Ministry of Rural Reconstruction for this purpose. Rural areas will be developed after the implementation of different schems meant for the rural upliftment. I would like to speak a word about Panchayat Raj system. Sir, there, was a three tier system of local self-administration. Zila Parishads, Blocks, and Gram Panchayats were functioning some years back. At present there are only local-self administration bodies in Orissa. Zila Parishads have been abolished. We want to decentralise power. So we cannot ignore the role of Zila Parishads. Sir I would like to refer the Balwant Ray Mehta Committee which has praised the role of the Zila Parishads. I urge upon the Government to reintroduce the Zila Parishads. The Block Development Officers are looking after the upliftment of the rural areas. A separate revenue unit should be opened and Block Development Officers should be given the dual responsibility of both the Development Officers and the Tehsildars. I would also like to give some suggestions about the powers of Sarpanchs. Sir, previously the Sarpanchs were given some judicial powers. They were given the powers of third class magistrate. Sarpanchs were deciding minor cases at the panchayat level. In order to give justice to the poor people, Sarpanchs should be given the summary trial power. Gandhiji had given the call to go back to the villages. It is high time for our Government to undertake all round development of the rural areas. Therefore, training centres should be opened to train the Sarpanchs, Ward Councilors and Ward Members. After training they can provide better administration to the rural people. The 20-point Economic programme should be implemented right from the panchayat level.

Now, I would like to speak something about land reform measure. Sir, the zamindari system was abolished in our country. But some ex-zamindars are still enjoying the zamindaris. They possessed large acres of landed property in other names. They are the bogus tenants. I demand that the Government abolish the intermediary system. A piece of legislation should be brought before the House for the purpose. Pattas were distributed to the landless people during our previous regime, but I am sorry that the Janata Government did not implement this programme. The Government has, however, decided to introduce this programme. I would request the Government to implement this programme with little modification. Sir, pattas have been distributed to the landless people. The total land they are getting is, however very little. These are the surplus lands. They are not improved lands and the poor who become owner spend more money towards cultivation than they actually get out of it. I hope that some guidelines will be sent to State Governments to allot some more acres of land to the landless people.

Landless agricultural labourers are also given the surplus land which Government acquires from the big landlords. This is not sufficient. Financial assistance must be given to such cultivators for tilling their lands. Labour cooperatives should be formed who should provide them with all possible assistance in improving their lands. It is fact that some people have land but their financial position does not allow them to invest money in their holdings. As a matter of fact, their land remain uncultivated. These fallow land should be taken away from them for the cultivation of the landless people. A comprehensive Bill for this purpose should be brought before the House. Consolidation of land programme

[Shri A. C. Das]

should be implemented vigorously. If we follow this programme our farmers will be benefited to a great extent and production will also increase.

Then I would like to discuss the implementation of minimum needs programme. Construction of village roads, adult education, removal of illiteracy, drinking water supply, medical facilities to the villagers and integrated housing schemes are included in this programme. Orissa is a backward State. There are many vilages which are not connected with roads. Many village roads have remained unprepaired. I urge upon the Central Government to allocate special assistance for the State of Orissa for the completion of the construction of the village roads. Each village should be connected by road. Drinking water should be supplied to every villager. Steps should be taken to spread education and eradicate illiteracy. Proper medical facilities should be given to each and every person living in the rural areas. Mobile health units should be opened in different villages. The State Government, the Central Government and the local people should bear the expenses equally. Pacca houses should be given to the poor and the houseless.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can speak on Housing Demand. It does not come under Agriculture. Agriculture Minister will not be able to reply to that.

SHRI A. C. DAS: According to the records I am speaking. It comes under rural reconstruction. Let me say something about the Nutrition Programme. It is good to supply nutritious food to our villagers. But the present system of supplying CARE food should be stopped. It is unnecessarily creating quarrel among the rural poor. By being so, we cannot remove poverty. Therefore I request the Government to give a deep thought on this system and some central guidelines should be sent to the State Government in this regard.

Sir, the wages given to the agricultural labourers in my State are very meagre. The prices of all essential commodities are going up every day. They will not be able to maintain their families with the present rate of wages. Therefore, I urge upon the Government to increase their wages to Rs. 7 per day.

Sir, I will be failing in my duty if I do not make a mention of inland fishing. Four districts of Orissa namely, Cuttack, Puri Balasore and Ganjam are coastal districts. Besides there is scope for inland fishing in the ponds, rivers and reservoirs of Orissa. Government should provide assistance for Pisci-culture in my State. If we do so the unemployed youth get job and they can strengthen the country economy. Orissa Government has requested the Central Government to allocate funds under this head. I hope that Central Government will pay attention to the request of the State Government. Finally, I would like to say something about the operation flood. There is a lot of scope in Orissa for implementing this scheme. Orissa Government has sent the feasibility report in this connection. A scheme has been prepared. Orissa Government has asked for Rs. 533.26 lakhs for implementing the operation flood. I hope that Central Government will look into it favourably. With these words I conclude my speech.

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : रूपि की मांग के सिलसिले में मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा।

पिछला साल हमारे देश में अकाल का साल तो था। उसके पहले दो साल काफी अच्छे उत्पादन के साल थे और इस देश के खाद्यान्न का उत्पादन करीब

122 मिलियन टन के पास पहुंच गया । इस बार काफी लम्बे चौडे दावे किये गये। यह कहा गया कि हम ने योजना में कुल 7340 करोड़ का प्रावधान किया है और यह प्रावधान पिछले साल के प्रावधान से 14.6 प्रतिशत अधिक है । रुपये की कितनी कीमत हो गई है और मंहगाई कितनी बढ गई है, इस को आपने देखा ही नहीं । रोज या हर सप्ताह जो आपके आंकडे निकलते है उनको देखने से पता चलता है कि पांच प्वाईंट प्राइस राइस हर सप्ताह हो जाता है। कुल मिला कर करीब 25 प्रतिशत दाम बढ गये हैं, मंहगाई बढ गई है पिछले साल जो कीमतें थी उनके मुकाबले में । आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते है कि इस योजना में 7340 करोड़ रुपये का प्रावधान कर के पिछले साल के मुकाबले में आपने रुपया बढा दिया है। यह असली 14.6 की बढत है । यह बढत है कहां ? यह सब घटत है ।

फिजीकल टारगेट, जिनका आम तौर से हर बजट में हमेंशा मैंने उनका प्रावधान देखा है कि इतनी दालें, रूई, धान पैदा करेंगे और इंडस्ट्रीज के टारगेट्स भी होते है। इस साल के बजट में आप देखेंगे कि जहां तक फिजिकल टारगैट्स का सवाल है, वहा बिल्कुल दबी जबान से थोड़ा सा इशारा किया गया है और कुछ नही कहा गया । यह भी लिखा है कि हमारा धान का लक्ष्य 120 मिलियन टन इस साल में होगा ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग एक आयोग है जिसे कांग्रेस की सरकार ने 5 साल पहले बैठाया था । उसने बड़ा सोच-समझकर एक रिपोर्ट दी, कुछ सिफारिशें की और सोचा कि इस देश में जनसंख्या किस रफ्तार से बढ रही है। जनसंख्या की बढती हुई रफ्तार को देखते हुए किस किस चीज के कितने उत्पादन की आवश्यकता रहेगी, इन सारी बातों का बहुत बारीकी से सारा सोच विचार कर के इस रपोर्ट में कुछ सुझाव दिय गये थे । यह भी सोचा गया कि 1985 तक इस देश में करीब 75 करोड़ की आबादी होगी और इस 75 करोड़ की आबादी को खाने के लिये 156 मिलियन टन अनाज इस देश को चाहिये । आज हम 1980-81 में 120 मिलियन टन अनाज पैदा करने की बात सोच रहे हैं और यह सरकार बड़ा गर्व करती है कि हमने बजट को पहले से बढा दिया। मैं समझता हूं कि यह परफार्मेन्स इस रफ्तार स इस देश को ले डूबेगी । आज जिस तरह के हालात इस देश में हो रह हैं, जनसंख्या बढती जा रही है, 70 करोड़ पर हम पहुंच गये,

एक माननीय सदस्य : आपकी ओर से विरोध हुआ था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ । सन् 1952 से मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे जानते नहीं हैं, कि जनसंख्या पर नियंत्रण अगर इस देश में नहीं किया जायेगा और उसके साथ योजना को नहीं जोड़ा जायेगा तो यह देश डूब जायेगा । यह मेरी बात आप सन् 1952 से देख लीजिये, आम मीटिंगों के मेरे भाषणों को सुन लीजिये। आप तो अभी आये है, जान नहीं रहे हैं मुझे ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कृषि आयोग की सिफारिशों के बारे में मैंने रैफरेंस में पूछा था कि किस स्टेज पर चल रही हैं। मेरे इस सवाल के जवाब में यह कहा गया कि 2361 सिफारिशें है, 1614 मान ली गई, 306 पर अभी काम हो रहा है और नौट रक्सैप्टेड 25 है और अंडर इग्जामिनेशन 416 हैं।

मैं सोचता हूं कि जिस गौर से इन सिफारिशों को लिया जाना चाहिये था, खासतौर से 2 सिफारिशों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज के बारे में है कि सैन्ट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम सैक्रेट्रीस से नीचे के जिलें लैवल तक सारी मशीनरी में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हो, और दूसरा चैप्टर इम्पार्टेन्ट है जिसमें लिखा है कि सैन्टर और स्टेट रिलेशन्ज इस नये दौर में क्या होने चाहियें ।

इन सुझावों में आज तक कुछ नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि आज वक्त है, आपका एक बैलरनिक सरकार का आर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स में चारो तरफ आपने अपनी सरकारें बना ली हैं। यह सैंटर और स्टेट में आपस में ताल-मैल करने कावक्त है वैसे आप जानते है कि कृषि राज्य का विषय है और आप नीति निर्धारण का काम करते है या कुछ पैसा सेंटर से देने की कार्यवाही करते हैं । वह पैसा आप उनको एलाट करते है, पर आपका और उनका आपस का ताल मेल कि किस प्रकार से पैसा खर्च होना चहिये और उन योजनाओं के जो परिणाम होने चाहियें, उनमे आज कतई नही है । जिस तरह की कार्यवाही आज आप करने की स्थिति में है वैसी कार्यवाही करने की स्थिति में जनता पार्टी की सरकार नही थी, और उससे पहले जब हमारी और आपकी सरकार थी वह भी इस काम को नही कर सकी । आज इस काम को करना चाहिये ।

14 hrs.

बहुत से माननीय सदस्य तो कृषि आयोग की रिपोर्टों के बारे में जानते भी नहीं होंगे। वे रिपोर्ट पुराने सदस्यों को दी गई थी। यदि नये मेम्बर साहबान को भी एक एक कापी पढने के लिये दे दी जाये, तो उन्हें भी मालूम हो सकेगा कि कृषि आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): A summary of it should also be distributed.

श्री नाथू राम मिर्धा : कृषि आयोग ने बहुत से विषयों पर बहुत जबर्दस्त रिपोर्ट दी है उसने समुद्र में पैदा होने वाली मछलियां, जानवरों, जंगलो और खेती से उत्पन्न होने वाली सब चीजों के बारे में रिपोर्ट दी है।

[श्री नाथू राम मिर्धा]

सिंचाई की मांगे इस मंत्रालय के साथ आती रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अब सिंचाई मंत्रालय को अलग कर दिय गया है। सिंचाई आयोग और कृषि आयोग दोनों ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि नदियों का पानी एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उस पानी का उपयोग देश की सारी जमीन को सिंचित करने के लिये किया जाना चाहिये।

14.02 hrs.

[Shri K. Rajamallu in the chair]

आज स्थिति यह है कि नदियां जिन इलाकों में से निकलती हैं, उन राज्यों का उन पर हक है। राज्यों का आपस में ताल मेल नहीं है और उनमें आपस में झगड़े होते हैं। इसी कारण हरियाणा में नहरे बिना पानी के पड़ी हुई हैं। इस बारे में संविधान में संशोधन करने के लिये एक कानून तैयार हो चुका है। जब तक संविधान में यह संशोधन नहीं किया जायेगा, तब तक राज्यों के बीच पानी के बारे में डिसप्यूट्स होते रहेंगे। कुछ डिसप्यूट्स निपटाये गये हैं। नर्वदा नदी का डिसप्यूट 14 साल के बाद तय किया गया है, और वह भी करीब करीब उसी लाइन पर तय किया गया है, जो पंद्रह साल पहले खोसला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। उस वक्त उस कम्प्लैक्स की कास्ट 1200 करोड़ रुपये थी। यदि आज इस योजना को शुरू करें, तो वह पंद्रह सालों में पूरी होगी। उस समय यह कम्प्लैक्स 12,000 करोड़ रुपये में पूरी होगी। अगर उसी वक्त इस बारे में फैसला हो जाता, तो देश का कितना भला होता। देश में सब से ज्यादा पानी रखने वाली नर्वदा नदी का फैसला आज हुआ है। जब तक सरकार इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी, तब तक इस देश में जरूरी काम नहीं होंगे।

कृषि आयोग और सिंचाई आयोग की सिफारिश के मुताबिक संविधान में संशोधन आज किया जा सकता है, क्योंकि आज राज्य सरकारें आपके हाथ में हैं, केन्द्रीय सरकार भी एक मजबूत सरकार है और इन्दिरा जी जैसी मजबूत प्रधान मंत्री हैं। इसलिये इस काम को अविलम्ब करना चाहिये।

राजस्थान कैनाल कितने अरसे से बन रही है। वह सारे देश की खाद्यान्न और कपास की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कृषि आयोग ने कहा था कि जहां आदमी रहते हैं, वहां पानी ले जाया जाये, बजाये इसके कि पानी को पाकिस्तान के बार्डर पर सैंड ड्यून्ज की तरफ ले जाया जाये, जहां कालोनाइजेशन का कास्ट बहुत ज्यादा होगा। कृषि आयोग ने कहा था कि लिफ्ट योजना बना कर पानी वहां ले जाया जाये, जहां आदमी बसे हुए हैं। जनता सरकार ने उस सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया था। इस सरकार को चाहिये कि वह इस महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार करके राजस्थान की लिफ्ट योजना को सिक्स्थ प्लान का अंग बना कर इंम्पलीमेंट करें। आज देश में हर चीज की कमी है, जिससे मंहगाई बढती जा रही है। इस योजना से उन चीजों का उत्पादन बढ़ेगा।

नर्वदा के पानी को डेजर्ट में ले जाना और राजस्थान कनाल के पानी को ऊंचे इलाकों में ले जाना बहुत जरूरी काम है। अगर इन योजनाओं को तेजी से पूरा नहीं किया जायेगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

आज हमारे किसानों की क्या हालत है। वित्त मंत्री जी ने राज्य सभा में भाषण देते हुए कहा है कि हम किसान की पैदा की हुई चीजों और इंडस्ट्रियल उत्पादन की कीमतों में पैरिटी कायम करेंगे। कब करेंगे? क्या सरकार के पास इसके लिये कोई मशीनरी है? पंद्रह गैरस से तो मैं इस बात को सुनता आ रहा हूं। आज भी इसके लिये कोई मशीनरी नहीं है। इस लिये पैरिटी का प्रश्न ही नहीं है। किसान की सब चीजें आप सस्ती लेना चाहते हैं और किसान को जो चीज भी आप दे रहे हैं सारी की सारी उस की इनपुट्स महंगी कर दी। किसान के ट्रैक्टर पर 45 परसेंट 46 परसेंट टैक्स है। एक ट्रैक्टर आज किसान लेने जाता है तो मय इम्प्लीमेंट्स के 80 हजार रुपये में मिलता है, क्या कोई किसान 80 हजार रुपये खर्च कर के ट्रैक्टर खरीद सकता है? और अगर इस देश में ट्रैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। कृषि आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि इस देश में तीन स्टेजेज पर मैकेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। पहले तो जमीन की जुताई के लिये ट्रैक्टर का सवाल है, फिर जमीन से पानी निकालने का सवाल है, लिफ्ट कर के पानी को इस्तेमाल करने का सवाल है और हार्वेस्टिंग के लवेल पर मशीनों के यूज का सवाल है। बड़ी गहराई से अध्ययन करने के बाद कृषि आयोग द्वारा यह राय दी गई है कि इन तीनों स्टेजेज पर ऐग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन तेजी से करने की जरूरत है। आज दाम बहुत बढ़ गये। किसान की मोटरें महंगी डीजल का भाव इतना बढा दिया, कुल मिला कर 21 सौ करोड़ का टैक्स आप ने लगा दिया है, 6–7 सौ करोड़ का टैक्स फर्टिलाइजर पर लगाया है, किसानों का फर्टिलाइजर ड्योढा महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, टैक्टर का दाम बहुत बढ गया, क्या चीज आप किसान को सस्ती दे रहे हैं? किस बुनियाद पर किसान से आप सस्ती चीजे पदा करने की आशा करते हैं और लोगों को सस्ती चीज दिलवाना चाहते हैं। आप दो चीजे कीजिये। या तो किसान को उपयुक्त दाम दीजिये या इनपुट्स के दाम कम कीजिये, इनपुट्स सस्ते दीजिये। आज एक भी चीज नहीं है। हर चीज किसान से तो सस्ती लें और किसान को सब चीज महंगी दें इस तरह से काम नही चलेगा। आप ने बजट के अंदर बड़ी सफाई से कह दिया .... (व्यवधान) ....मैं आप से निवेदन कर रहा था कि किसान के बारे में परिटी इन प्राइसेस होनी चाहिये। किसान को इनपुट्स के अंदर जो चीजें

आप दे रहे हैं वह कितनी महंगी हो गई है, बहुत गहराई से माननीय मंत्री जी को इस पर सोचने की जरूरत है और यह कृषि आयोग की रिपोर्ट है, इरीगेशन की रिपोर्ट है, इस को देखें।

कई बातें हैं खास तौर से बैल और गौ वंश का क्या हाल हो रहा है? विनोबा जी रोज उस के बारे म कहते हैं। इंदिरा जी की भी उन से बातें हुई है और आप लोग भी उस के बारे में कहते रहते है। गोवंश को जब तक इस देश में आप ऊंचा नही उठाएंगे और उन के गले पर से छुरी नही उठायेंगे तब तक इस देश के अंदर कभी भी आप सुखी और खुशहाल नही हो सकते हैं। यह मेरी कोई पोलिटिकल मांग नहीं है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप को 14 हजार मिलियन बैल इस आने वाली सेन्चुरी के अंत तक चाहिये अगर किसान से ठीक ढंग से आप खेती करवाना चाहते हैं। यह बड़ा अहम प्रश्न है। बैलों की शक्ति को भी आप को बढाना होगा और दूसरे तरह के पावर को भी बढाना होगा ज्यादा समय दे नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ने इशारे में बातें की हैं ....(**व्यवधान**)...मुझे खुशी हैं कि आप मेरी बात पसन्द कर रहे है।

मैं खास तौर से कुछ गरीब मछुओं और फिशरीज के बारे में कहना चाहता हूं। फिशरीज में बराबर इन पिछले सालों में टैक्स घटना चला जा रहा है और वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। वैल्यू बढने से आप कहेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन ऐक्चुअल कैच हमारा घट रहा है और वह इसलिये घट रहा है कि छोटे लोगों के पास भी मैकैनाइज्ड बोट्स हो गई। यह सवाल कई दफा आप के सामने भी आता है और बड़े ट्रालर्स भी हो गये। तो ट्रालर्स दूर जाना नही चहते क्यों कि दूर जाना महंगा पड़ता है, डीजल के दाम और कई चीजों के दाम बढ़ गये है। डीप सी में जा कर वह कैच करते नही है। वहीं नजदीक में ही दोनो लड़ते है। मैं कहना चाहता हूं कि समुद्र का वेल्थ हो यह काफी बडी मात्रा मे हिन्दुस्तान के अंदर भी खाने के काम आयेंगी और बाहर भी भेजी जा सकती है। तो इस तरह की जो खाने की चीज है उस को आप बढ़ाते नही है उसको तो आप बढ़ाएं।

इस बात को मैं फिर जोर दे कर कहना चाहता हूं कि इस देश मे खास तौर से गौ वंश की रक्षा होनी जरूरी है। इस देश में गऊ नही कटनी चाहिये और कही नहीं कटनी चाहिये। फाडर और चारे के बारे में बहुत योजनाये दी है।

फारेस्ट्स के बारे में भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। इस कमीशन की रिपोर्ट में 8 रिपोर्टे फारेस्ट के बारे में हैं और खास तौर से डेजर्ट डेवलपमेंट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। डेजर्ट डेवलपमेंट के अंदर पिछले साल योजना में आप ने 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। क्यों कर दिया? इसलिये कर दिया कि 9 करोड़ राज्यों वाले फाइन्ड आउट करें। 18 करोड़ की पूरी सेन्ट्रली फाइनेंस्ड स्कीम इसलिए रखी थी कि यह इलाके देश के पिछड़े हुए इलाके हैं। इनमें 11 जिले राजस्थान के हैं, 4 जिले गुजरात के हैं और 4 हरियाणा के हैं। इसी में लदाख और लाहोलस्पीति का इलाका भी है। यह सब पिछड़े हुए इलाके है इसलिये डेजर्ट डवलपमेंट के लिये केन्द्र की तरफ से आपको पूरा धन खर्च करना चाहिये। लेकिन आपने भी जनता पार्टी की नकल कर ली, आप उसमें कोई परिवर्तन नही लाए। पिछले साल 9 करोड़ का प्राविजन था और खर्च किया 5-6 करोड़ और इस साल आपने 8 करोड़ का खर्च रख दिया। यह डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल डेवलपमेंन्ट प्रोग्राम वगैरह कमीशन की रिपोर्ट में इस दृष्टि से सजेस्ट किये गये थे कि वे स्पेशल इलाके हैं, बैकवर्ड रीजन्स हैं जहां गरीब लोग रहते है इसलिए इन योजनाओं को पूरा करने के लिये सेन्टर को विशेष तौर से आगे आना पडेगा और कार्यवाही करनी पडेगी।

जहां तक फारेस्ट की बात है, उस के बारे में हमने रिपोर्ट में दिया था कि मैनमेड फारेस्ट से लोगों को एम्पलायमेंन्ट मिलेगा। यहां पर रात दिन एम्प्लायमेन्ट के बारे मैं चर्चा होती रहती है। हमने कृषि आयोग रिपोर्ट मे सारा वर्कलोड बताया था कि कितना एम्पलायमेन्ट दे सकते हैं अगर योजनाबद्ध काम किया जाए। परन्तु डिटेल में किसी ने भी इन योजनाओं को नही देखा, केवल कुछ बातों को पकड लिया। इस तरह से अधूरी योजनायें चल रही हैं।

आपको डिटेल में सारी योजनायें लेनी पड़ेगी मार्केटिंग के बारे में भी देखना होगा ताकि आप किसान को वाजिब कीमत दिला सकें। किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पडती है। भण्डारण के लिए गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे। आपने कुल मिलाकर 9 करोड़ का प्राविजन किया है जिसमें पिछले साल 3 करोड खर्च किए गये। मार्केटिंग के बारे में कृषि आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि जबतक मार्केटिंग की, हाट बाजारों की व्यवस्था नही होती किसानों की लूट खसोट होती रहेगी, उसको सही दाम नही मिल सकेगा। इसलिए मार्केटिंग के बारे में जो रेकमेंडेशन्स है उनको सही ढंग से लागू किया जाये, उसी के हिसाब से उचित प्रावधान किये जायें तथा जो प्रावधान किये जाए उस पैसे का खर्च किया जाए। आप देखेंगे कि कृषि से सम्बन्धित बहुत सी मदों में पिछले साल जो पैसा रखा गया वह खर्च नही हुआ और इस साल आपने उसको कम कर दिया। जैसा कि दिगम्बर सिंह जी कह रहे थे एनिमल हस्बैन्डरी में आपने बढ़ा दिया है, लम्बे चौड़े प्लान्ट्स लगाए जायेंगे लेकिन जानवरों की नस्ल सुधारने के लिये, उनके लिये चरागाह बढाने के लिए, उनकी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए कोई प्राविजन नहीं किया गया है। बड़े बड़े प्लान्ट्स भी जहां पर लगाने की जरूरत है वहा पर नहीं लगाये जाते हैं।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

गन्ना जलाने की जो नौबत आई वह इसलिये आई कि गन्ना क्रश नहीं किया गया। बड़ी शुगर मिलें थीं नहीं और जो छोटी यूनिट्स थीं वह गन्ना खरीद नहीं पा रही थीं। इसीलिए आज यह चीनी की मुसीबत आई। इस साल आपने कितनी चीनी मिलों का प्रावधान किया है? कितनी मिलें लगाई जा रही हैं। कोआपरेटिव सेक्टर में जो मिलें लगाई गई वह चलती नहीं है। कोआपरेटिव मिलें अभी फेल हो रही हैं। ऐसी हालत में जबतक आप किसान के उत्पादन की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की ठीक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्याज कभी एक रुपये की पांच किलो और कभी पांच रुपये किलो यह क्यों होता है? इसलिये कि मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। यही सब्जियों का भी हाल है। इसलिये आप मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें। आप यह भी देखें कि क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जायें। मैंने निवेदन किया था कि भेड़ और बकर का मांस जो बाहर जाता था वह भी आज बन्द हो गया है। किसान अगर मरता है तो मरे, उसका कोई इलाज नही है। इन सारी चीजों पर जबतक कृषि मंत्रालय ध्यान देकर काम से मिनिस्ट्री और दूसरों की वृद्धि ठीक नही करेगा जबतक स्थिति नहीं सुधरेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : ठीक कर रहे हैं।

श्री नाथुराम मिर्धा : : आप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आख मीचकर कर दिया जाता है। सभापति जी, आपने मुझे इतना समय बोलने के लिये दिया, इसलिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरी बातों को दिलचस्पी से सुना और उम्मीद है कि मंत्री जी भी मेरी बातों पर गौर करेंगे और देश के कृषि उत्पादन को आगे बढाने की कृपा करेंगे।

*SHRI H. N. NANJE GOWDA (Hassan): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and Rural Reconstruction.

In the first instance, I would like to take up rural reconstruction and express my views on it. Sir, in the rural areas people are not very much ambitious for freedom of speech. They are not very eager either to wear good clothes. But Certainly they are very much concerned about their living. They want to survive. God is graceful to give air. But, we have to provide an environment in which the villagers could get water. We are also committed to provide food and clothing to the people of this nation, Rural development has still to take place in this country. Rural reconstruction is the path of progress of our nation. But, if you look at the condition of the villages existing in our country, you will find that about 60 per cent of the villages are like slum areas. There is no development in these areas. There is neither any sanitation nor any public health programme. Rural reconstruction has become a dream. For centuries and now even after independence this remained a dream. Today if the millions of our rural population have to survive, there must be rural reconstruction, since this is the only answer to the problem. There is no drainage system in the villages. Streets have been converted into drains. This is the actual position of the villages. I would like to know why no priority has been given to the improvement of these villages? More than 50 per cent of the villagers are facing the problem of mal-nutrition. Many of them are anaemic on account of mal-nutrition. They are surrounded by dirty envirous. Even the most essential commodity like drinking water is not available to them. Our nation's wealth is its man power. But unfortunately, this gigantic man power is being wasted. About 20 per cent villagers have just some type of work or the other. About 30 per cent of the villagers have only 3 months' work in a full year. The rest of the people have no work to do at all. Today even the sweepers can agitate against the Government. If they do not do their duty, then the Government has to plead with them. Villagers who constitute 46 crores of our population are not organised. We win the elec-

*The original speech was delivered in Kanneda.

tions through the votes of these people. Today an industrialist had come to discuss with me his personal maters. But a Gowda (village farmer) cannot come here and discuss his problems with us. So far, the villager has not been taken care of. We must be sympathetic to him. This is my earnest request to the entire House. As I have already stated many of the villagers are without work. And even those who have some work are migrating to different places. I want to know why such a system prevails. The nation's wealth is concentrating in cities only, and there is nothing left in the villages. Today there is nobody to curb the bulging coffers of big people like Tata and Birla. They have "sheltered" markets. They can do anything and can sell their products at any rate they choose. On their products like tooth paste, and other such items there will be 500 per cent profit. This is the type of environment that has been created by these capitalists. Well, on the other hand the farmer and his wife work for the whole day. but unfortunately, they are not getting any returns for their hard labour. There is no value of the farmers' sweat and blood. Due to shortage of foodgrains we have to import food from outside.

Sir, fixing up of procurement prices is not a happy practice. It is not done on scientific basis. While fixing up the procurement prices the cost of the land should also be kept in mind. I urge the Government to constitute a Committee to look into the process of determining the procurements prices. The farmer should get a remunerative price. It should also be the prime duty of the Central Government to buy the agricultural products. At present the farmer is not sure of any price he would get for his agricultural products. Therefore, the Government should give him the assurance that it would buy his products at remunerative prices which would remain stable for a period of five years at least.

Water is the main input for agriculture. We had five Five Yea Plans. There were 23 million hectares of land for which irrigation facilities were available. Now, after implementation of 85 year pledge this number has increased to 43 million hectares. In some parts of the country there is drought. In some places, there is no sufficient stock of foodgrains. We import foodgrains from outside. But 80 per cent water of our rivers directly flows into the sea. What a travesty!

We do not have a national water policy. We have not fixed the priorities. We have not given any guidelines to any tribunals as to how they should function. We see so many discrepancies in the decisions of so many tribunals. I have studied the awards of the Krishna Tribunal, godavari, Tribunal and other tribunals. There are discrepancies because they do not have any guidelines to function. How can there be guidelines without a national water policy? There in Karnataka we are having 17 per cent irrigation, in Andhra 38 per cent, in Tamilnadu 42 per cent, in Maharashtra 39 per cent and so on. We do not know whether the Government of India is going to take any decision about this and declare a national water policy fixing priority. I want an assurance from the Government because if we completely exploit the water that is going waste into the sea, I am sure more than 120 million hectares can be brought under irrigation. What other wealth do you want in this country? Why not enunciate your policy and have a time-bound programme?

Finally, I urge upon this Government to clear the pending projects. So many projects from my State of Karnataka are pending clearance. Can you imagine that from 19 years projects are pending clearance here? It has become a burden on the State exchequer because they have to be taken outside the plan. Why is such a thing happening? It is because of

[Shri H. N. Nanje Gowda]

the bureaucracy. The bureaucracy must be whipped. The bureaucracy in this country have become a huge monster of inactivity and irresponsibility. They must be properly brought to order. Otherwise, whatever decision any popular Government takes to help the downtrodden people in this country, the results will never reach the people because of the inactivity and irresponsibility of the bureaucracy. I also advise the Government to fix responsibility on the officers for completing a time-bound programme—for such and such work, so many days. In China—I do not say that we should adopt the same thing here, but I am just giving an example—if there is any lapse on the part of any officer, he will be knocked on the head and shot in the stomach. So, the bureaucracy must be brought to order and they must be made to function. Otherwise, even after 33 years of independence, there is so much red-tapism. Unless you clear this, you cannot make the benefits reach the common man.

With these words, I conclude.

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : सभापति जी, सदन के समक्ष कृषि विभाग की जिन मांगों की चर्चा हो रही है, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करते वक्त मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन की गति, चाहे कितनी भी नुक्ताचीनी करें, लेकिन एक बात माननी होगी, काफी तेज हुई है और हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे है। पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन हमारी आश्वयकता से ज्यादा था, जिस में से हमने बाहर मुल्कों को भेजने की भी कोशिश की और उसके भेजने के बाद भी हम ने अपने देश को लोगों को काफी अच्छी मात्रा में अनाज देने का बन्दोबस्त किया।

इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं कि हम जिस विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे है, असल में वह 4–5 विभागों का एक समूह है। इस के बारे में यह बताया गया है कि इस के लिए बजट में 14 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। आज देश में कृषि के लिये पर्याप्त साधनों की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा।

मैं सब सदस्यों के भाषण को सुन रहा था। देहात के बारे में जो अखबारों में आता है उसे भी मैं पढ़ रहा था. इस बजट के बारे में जो देहात के अखबारों में लिखा है उसे भी पढ़ रहा था। इस बजट में शहर के लोगों के लिए भी रखा गया है, अरबन पापुलेशन के लिए भी रखा गया है। लेकिन जब किसान इस बजट की ओर देखता है तो मैं स्वयं मुश्किल में पड़ जाता हूं यह जानने के लिए कि इस बजट में किसान के लिए क्या रखा गया है। किसान के काम आने वाली जो चीजें है उनकी कीमतें बढी हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन किसान जो माल खरीदता है उसकी भी कीमतें बढी हैं। इसलिए आज किसान हम से असन्तुष्ट है और नाराज है। उसकी नाराजगी का सवाल यह है कि किसान जो उत्पादन करता है उसके लिए हमें यह देखना होगा कि उसे हम उसके उत्पादन की रेम्युनरेटिव प्राइसिज देते है या नहीं देते हैं। एक और किसान जो चीजें खरीदते है उन के दाम बढ़ते जा रहे है और वह जो गैहूं और ज्वार पैदा करता है उसके दाम वैसे ही हैं, वह जो कपास पैदा करता है उसके दाम वैसे ही है। इस तरह से उसके काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ने से उसकी उपज का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है और उसकी उपज की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें उसके द्वारा उत्पादित की हुई चीजों के दामों को निश्चित करने की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

जैसा अभी एक सदस्य ने कहा उनकी मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हुं कि जो कृषि सिंचाई से नही होती है उसे ड्राई फार्मिंग कहते है। मैं जिस स्टेट महाराष्ट्र से आता हूं उसमें 10 फीसदी हां खेती सिंचाई से होती है बाकि की बची हुई खेती ड्राई फार्मिंग है। ड्राई फार्मिंग में किसान साल में एक बार फसल ले सकता है। ऐसे किसान को जो आठ नौ महीने फसल नहीं ले सकता है, उसको अगर हम उचित मूल्य उसके मांल का न दें तो उसके लिए जीना असंभव हो जाएगा, व्यवसाय करना असम्भव हो जाएगा, इस लिए यह जरुरी है कि हम अनाज के जो दाम निश्चित करते है कापास के जो दाम निश्चित करते है उनमें वृद्धि करना बहुत आवश्यक है।

वे लोग संगठित नहीं है, किसानों की कोई ट्रेड यूनियन नहीं है इसलिए उनकी हड़तालें भी नहीं हो सकती है। वे आवागमन के साधन भी नहीं रोक सकते है। न उनके पास प्रेस है जिसमें कि वे पब्लिसिटी करा सके। हम प्रेस में भी देखते है कि किसानों की तरफ जितनी प्रेस सहानूभूति दिखानी चाहिए उतनी सहाभुभूति वह नहीं दिखाता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब जब किसानों की बात कही जाती है तो कुलक की बात सामने आ जाती है। जहां तक मेरे राज्य का सवाल है हमारे राज्य में लैण्ड रिफार्म्स पर सौ फीसदी अमल हुआ है। वहां कोई कुलक नहीं बचा है। जिन राज्यों में लैण्ड रिफार्म सौ फीसदी नहीं हुए है उनको देखकर यदि इस परिणाम पर पहुंचा जाए तो यह ठीक नहीं है। उन राज्यों को देख कर सभी किसानों की गणना कुलक में नहीं की जा सकती। यह भेद प्रेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब जब किसान का वर्णन होता है, वह कुलक और जमींदार के नाते किया जाता है। जिन राज्यों में सौ फीसदी लैण्ड रिफार्म्स पर अमल किया गया है उन राज्यों के किसानों को हम कुलक नहीं कह सकते जिन राज्यों में लैण्ड रिफार्म्स पर सौ फीसदी अमल नही हुआ है उन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लैण्ड रिफार्म्स पर अमल होना चाहिए।

एक बात के लिए मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि कुछ दिनों में हमारे महाराष्ट्र राज्य में केन्द्र सरकार ने अपनी समाजवादी नीतियों को ध्यान में रखते हुए कोटने मोनोपोली परचेज योजना को सहायता दी है। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि इस योजना को जहां तक हो सके और आगे बढ़ाया जाए। इसे दूसरे राज्य में भी बढ़ाया जाए। लेकिन साथ ही किसान को जो चीज या माल खरीदना पड़ता है उनकी कीमतें भी निर्धारित की जाए। जो मिल मालिक उन्हें पैदा करते है उनका मुनाफा भी निर्धारित किया जाए। इस योजना पर दूसरे राज्यों में भी अमल किया जाए। इस को करते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि किसान को जो चीजें दी जाती हैं और किसान को जो चीजें ली जाती हैं उन की कीमतों में कुछ सन्तुलन हो। अर्थ मंत्री जी ने राज्य सभा में एक बात कही थी उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रीज में जिन चीजों का उत्पादन होता है उनकी कीमतों में और खेती से पैदा होने वाली जो चीजें हैं, उनकी कीमतों में सन्तुलन रखा जाएगा, पैरिटी रखी जाएगी। लेकिन आज यह यह पैरिटी बिल्कुल नजर नहीं आती है। नेशनल इकोनीमी में यह बैलेंस आफ दि प्राइसिस होना चाहिये। किसान को उद्योग में पैदा हुई चीज बहुत महंगी खरीदनी पड़ती है और अपना उत्पादन जब वह बेचता है तो उसको उसे बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है। अगर यह पैरिटी नहीं लाई जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि किसान में और भी ज्यादा असन्तोष पैदा होगा। यदि देश का उत्पादन बढ़ाना है और किसान के उत्पादन को थोड़े सस्ते में भी लेना है तो यह आवश्यक है कि जो उत्पादन करता है, उसको कुछ इंसैंटिव दिया जाए और ऐसा कुछ हद तक खाद की कीमतों तथा खेती के काम आने वाले औजारों की कीमतों को कम करके किया जा सकता है।

इस वर्ष खास कर महाराष्ट्र के विदर्भ के हिस्से में सोइंग सीजन में किसान को बहुत तकलीफ हुई है सीड के मामले में। सीड कारपोरेशन के पास सीड नहीं था। अब प्लानिंग में क्या गलती हुई मुझे मालूम नहीं। लेकिन किसान को दूसरी जगह से प्लेन से सीड ले जा कर तकसीम करना पड़ा है और कुछ जिलों में तो सीड मिल ही नहीं सका। यह क्यों हुआ और प्लानिंग में क्या गलती रही इसकी इनक्वारी की जानी चाहिये, जांच पड़ताल की जानी चाहिये, ताकि अगले साल सोइंग के वक्त किसान को खास कर कपास, ज्वार और गेहूं के लिए जो हाईब्रिड सीड चाहिये वह उपलब्ध हो सके। ऐसे भी मौके हमने देखे है जब प्राइवेट व्यक्ति को सीड बेचने का कांट्रक्ट दे दिया गया और उन लोगों ने बहुत मुनाफा कमाने की कोशिश की जिसकी वजह से किसानों में काफी असन्तोष पैदा हुआ। कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं। मैं समझता हूं कि वह स्वयं इस मामले की तहकीकात करेंगे और किसान को राहत देने की कोशिश करेंगे।

चीनी का सवाल भी यहां उठाया गया है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो चीनी पैदा करने में अग्रसर है। महाराष्ट्र की सहकारी क्षेत्र में कई शूगर फैक्टरीज स्थापित करने की योजना है। दूसरे राज्यों का तो मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में सहकारिता के क्षेत्र में शूगर मिलें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और बहुत अच्छा चीनी का उत्पादन करती है। महाराष्ट्र सरकार ने कई शूगर मिलों के वास्ते योजनाये बना कर केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं जो यहां पड़ी हुई हैं। यदि केन्द्रीय सरकार उन योजनाओं को अपनी मान्यता दे दे तो चीनी का मसला हल करने में काफी मदद मिल सकती है। इस ओर भी केन्द्रीय सरकार ध्यान देगी, ऐसा मैं समझता हूं।

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): Mr. Chairman, Sir, in discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture, one feels that the absence of Irrigation has caused certain erosion in the importance of this Ministry because Irrigation and Agriculture should have been discussed together. By adding the Ministry of Rural Reconstruction to the charge of the Minister, I think the importance of the Ministry has gone very high and it is a most importance subject today.

Sir, agriculture is the backbone of Indian economy and 70 per cent of the people depend on land for their living. 49 per cent of the national income is derived from agriculture. The agri-

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

cultural sector also supplies raw material to the industrial sector. And you are right in saying that agriculture has the potential of doubling its production. Dr. Swaminathan and Dr. S. K. Sinha have said that there is a great potential in agriculture, and we can double our production.

Just now, the Chairman of the National Commission on Agriculture was telling us about the various recommendations made by the National Commission on Agriculture. They have also stated that agriculture is capable of producing foodgrains enough to feed a population of 900 million in 2,000 A.D., but the question is whether there will be demand for it, whether the people will have the purchasing power, and whether the agriculturists will actually have the necessary impetus to double production.

We all know that the agriculturist has been neglected. Every speaker who has participated in this debate has spoken about the need for giving remunerative prices to agricultural products. It has been agitated on many platforms that the agricultural produce is not being paid its proper price, and there is need for having a parity between the prices that the agriculturist pays for his consumer goods and the price that he receives for his produce. And that explains the wide gap between the performance and the potential of agriculture because you will notice that our average production is lower than that of other countries and is perhaps the lowest in the world. But in our national demostration plots, production is comparable to the best in the world. Therefore, there is need for providing the necessary impetus to the agriculturist.

The Janata Party Government felt that agriculture needed top priority and it did give it higher priority. You will notice that after the decision that we took to discontinue imports, food production picked up. In 1977-78 we reached a production of 125 million tonnes. In 1978-79 it went up to 131 million tonnes, but due to drought in 1979-80 perhaps there will be a decline. All the same, we introduced a change in thinking.

The Finance Minister also in his Budget speech has recognised and acknowledged the importance of agriculture and its performance in relation to the development of the country, but despite his open acknowledgement, many of the schemes that have been introduced for helping the poor people and for improvement of agriculture receive niggardly assistance from him. Yesterday, Mr. Digambar Singh, while speaking on the subject, mentioned the various schemes which have received less allocation than what was allocated in 1979-80.

The Finance Minister spoke about the national rural employment scheme. This Ministry is now charged with rural reconstruction. The magnitude of the problem of rural unemployment is a big challenge before the Ministry and before this country, and until we introduce schemes to absorb the labour force, we will not make any headway or progress. As I have already mentioned, even if we have the potentiality of doubling our production, if there is no purchasing power in the hands of the people, there will be no demand. The agricultural production will not pick up. Therefore, there is the necessity for introducing schemes for providing employment to the rural poor. From our estimates, we find that in 1978, the number of unemployed rose to 20.6 millions and it is the concern of the Government to provide them employment. Many schemes were introduced, but unfortunately, they have not made any dent. National Rural Employment Scheme, about which the Finance Minister has spoken, will also not succeed unless a proper machinery, to implement the various schemes, is

created. We should have resource inventory at the block level. We should introduce micro-planning at the block level. Unless we identify the problem, it will not be possible for us to find a solution for it. We should create adequate infra-structure to absorb the funds provided for the various schemes and to execute them.

With regard to agriculturists, I have a few suggestions to make. I have already said that they are not receiving the prices that they should. One of their main handicaps is lack of warehousing facility. There is need for expanding the warehousing facility which should almost be taken to the door-step of the farmer so that he can store his produce and sell it at a higher price when the prices go up, and not immediately after the harvest. This facility should be given to the farmers.

Coming to ICAR, they deserve congratulations for introducing high yielding varieties, which are being exported and they have got appreciation from all over the world. I would like to invite their attention to the problem of undertaking research work for having an integrated farming system. They have spoken about taking the research from lab to land and they have thought of approaching only 50,000 families a year. The extension machinery will have to be strengthened and energised so that the results of research are carried to the farmer. The Indian farmer is segacious and intelligent enough, he has got commonsense and if you explain to him the benefits of adopting new technology, he will do so. Therefore, there is need for strengthening the extension machinery. Our concentration has so far been on introducing high yielding varieties. I would like them now to concentrate on evolving an integrated farming system. Supposing a farmer has 5 arces of land, he should be told what blend of farming he should have, what kind of cropping system he can have. He can raise three crops, but at the some time, in order to supplement his income, he can take to dairy farming, poultry farming or piggery. This would help to augment his income and at the same time, it will cut down the use of fertiliser. The withdrawal of subsidy on fertiliser has created a big problem to the farmers. Now the farmer will have to pay Rs. 600 crores more for the same level of consumption as last year. You can well imagine the burden the farmers will have to bear now. There are about three million pumpsets which are dieselised. but the diesel prices have gone up. If you make a rough computation of the extra price, the farmer will have to pay Rs. 300 crores more. So, the total additional burden on the Indian farmer will be about 900 to 1000 crores of rupees. You can well imagine the position of the Indian farmer. Therefore, if all the other subsidies are remaining, you should also consider the question of restoring the subsidy on fertiliser. Otherwise, the consumption of fertiliser will be cut down by a million tonnes. with the result foodgrains production will fall down. There will be a decline of 10 million tonnes. The country will have again to go back to where it was in 1976-77. It will have to depend on imports and will not be self-sufficient. If we have to be a big nation, a great nation, we have got to acquire self-sufficiency in foodgrains. We should be able to produce enough not only to feed ourselves but even to export to other neighbouring countries which need foodgrains. Therefore. I would urge upon the Agriculture Minister to consider the question of restoring subsidy on fertilisers and, secondly, he should also consider the question of restoring cuts in regard to several schemes like drought-prone area programme, command area development programme, small and marginal farmers development agency programme, etc. Wherever there has been a cut, it should be restored if you really mean business. If you

[Shri Satyendra Sinha]

want the national rural employment scheme to succed, it cannot be succeed only by having food for work programme. You will have to take up all the programmes. Then alone, you will the able to provide work to the rural poor. It is estimated that by 2000 AD, there will be at least 111 million people in the rural force for whom you will have to provide work.

The National Commission on Agriculture says that it will not be possible for you to provide work for more than 58 million people, and for the rest, you will have to find work elsewhere. Therefore, alongside agriculture, you have also to develop small-scale industries. You should adopt the strategy which the Janata Government adopted for eradicating poverty in the country. I would like to know from the Agriculture Minister whether this Government has made any commitment about the time-frame within which they dispose to eradicate poverty from this country as we had done during the Janata regime.

श्री राना वीर सिंह (केसरगंज) : सभापति महोदय कई दिनों से सुन रहा हू कि यह कृषि प्रधान देश है, यहा की जनता गावों मे रहती है और साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी कृषक है, स्पीकर महोदय कृषक है, माननीय कृषि मंत्री जी कृषक है और इतना मैं और जोड़ना चाहता हू कि जो वर्तमान समद है, शायद इतिहास मे सब से अधिक सभासद भी उसके इस वक्त कृषक है। यदि आज कृषकों की दशा नही सुधरती तो हमेशा के लिए कृषकों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। अभी हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य सिन्हा साहब बोल रहे थे। उन्होंने जनता पार्टी के महान प्रयत्नों की कुछ चर्चा की है मुझे भी आकर्षण हुआ कि मैं भी दो चार शब्द उत्तर में कहू हम ने तो इतना विश्वास किया था कि हम ने अपनी सारी कुछ सम्पदा सारा देश समर्पित कर दिया था उस किसान के बेटे को जिस के नेतत्व मे आप काम कर रहे थे और जो धोखा हमारे साथ हुआ उसकी कुछ झलकिया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हू। उसी प्रोग्राम के बारे में जिसकी कहानी आप ने कहीं है कि आप गरीबी दूर करना चाहते थे उसी के विषय में मेरा विनम्र निवेदन थोड़ा सा होगा, कृप्या सुनने का कष्ट करें।

पहली बात मैं प्रस्तुत करना चाहता हू मेरे जिले में एक बड़े भारी नेता आप के गए थे, उनका नाम लेने में मुझे कुछ हिचक नही है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होने कृषको को भुलावा देने के लिए कहा था, कि हमारा शासन आने पर हम 150 रुपये क्विंटल गेहू खरीदेगे। मैं कृषक हू। मुझे आज तक आपकी वह दुकान नही मिली जहा। 50 रुपये क्विटल गेहू मेस खरीदा जा सके। आप ने कहा था कि जो भी तुम उत्पादन करोगे उस का सब कुछ खरीदने का हमारा पूरा उत्तरदायित्व होगा। हम ने आलू का उत्पादन किया आलू का उत्पादन इस तरह से किया गया और उसके विपणन की दुर्व्यवस्था ऐसी रही कि मेरे ख्याल मे कीर्तिमान इस देश के कृषि के इतिहास में आपकी पार्टी के लिए एक शर्मनाक अध्याय रहेगा। आलू को रखने की जगह नही थी। शीत भंडार भरे हुए थे और आलू रखने का कही स्थान नही था। फतेहगढ़ मे जिन किसानों ने ऋण लेकर आलू की खेती की थी उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी और स्त्रियों की क्या दशा हुई, मैं कहना नही चाहता।

इसी प्रकार से गन्ने का जो एक्सपैंशन किया गया उसका प्रायश्चित आज हमारी सरकार कर रही है। श्री चरण सिह जी मेरठ के है, गन्ने की हालत यह हो गई थी कि उसको खरीदने का आप के पास साधन नही था, कृषक यहां पर आकर आपसे और कृषि मत्री जी से निवेदन करते थे और कहते थे कि हम आपसे और कोई काम नही कराना चाहते, आप कृपा करके चले चलिए और हमारे खेत मे दियासलाई की एक तीली जलाकर लगा दीजिए। जब किसानो को गन्ने का दाम नही मिला तो उन्होने गन्ना बोने से अपना हाथ खीच लिया आज आप यहा पर सरकार को उलाहना दे रहे है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हू कि यह आपके पाप है जिनका प्रायश्चित हमारी सरकार कर रही है।

दूसरी बात यह है कि आप बिजली के कनेक्शन देते चले गए लेकिन आपको यह पता नही था कि कितनी बिजली का उत्पादन होगा। मैं भी एक कृषक हू। आपने बिजली के कनेक्शन बढ़ाने शुरु कर दिए और उसके बाद मीटर हटवा दिए। आपका केवल क ध्येय था कि किस तरह से किसानों को लूटा जाए। अगर मीटर लगे होते तो आपकी अकर्मण्यता और अकुशलता का पता चल सकता और हम जान सकते कि आप कितनी बिजली दे रहे है और कितने दाम वसूल रहे है। आपने दाम फिक्स कर दिए आपने बिजली केवल दो घंटे दी और दाम पूरे वसूल किए जितने तय कर रखे थे। अभी एक बड़ी विचित्र बात कही गई कि आपके कार्यकाल में उत्पादन बढ़ा मैं आपके सामने एक बड़ी एथारिटी का उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हू।

No less a person than the President of the World F.C. who spoke at Brussels on February 18, 1980 said:

"Among the developing regions, food production fell most sharply in South Asia, primilarily the result of a decline in India's production".

यह आपके कारनामे है जो मैं बता रहा हूं कि कितना ऊंचा उत्पादन चला गया था।

अब मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से कुछ कहना चाहता हूं आज का जो विषय है उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ रूरल रिकांस्ट्रक्शन भी है। रिकांस्ट्रक्शन एक बड़ा उपयुक्त शब्द है। आज रिकांस्ट्रक्शन केवल आपको ग्रामों का नहीं करना है बल्कि सरकार के प्रति कृषकों के विश्वास को भी रिकांस्ट्रक्ट करना है। आज उसका विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है इसलिए उसके विश्वास को भी रिकांस्ट्रक्ट करना है। मंत्री महोदय मुझे दया आती है जब मैं कहता हूं कि इतना बीमार, मरीज कृषि का अर्थ-तंत्र आपको मिला है। इस बीमार अर्थतन्त्र को क्या दवा दें, एक शिल्पकार की तरह से इसकी तस्वीर में कैसे नये रंग भरें—यह आपकी ड्यूटी है। एक कृषक होने के नाते पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद कृषि ही एक ऐसा उद्योग है जिसमें उत्पादन तो आप हम से कराते हैं और उसके दाम दूसरे से तय करते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा उद्योग नहीं होगा जहां उत्पादन कोई करे और उसे उत्पादन का भाव कोई दूसरा तय करे। मुझे भी यह अधिकार मिलना चाहिये कि जहां मन्त्री जी और उनके सरकारी वरिष्ठ अधिकारी हमारे उत्पादन का मूल्य तय करने बैठें, उन मे भी हमे बोलने का मौका मिले।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके इतने सरकारी फार्म देश में चल रहे है, क्या कोई भी सरकारी फार्म ऐसा है जो लाभ मे चल रहा है? अगर लाभ में नहीं चल रहा है, तो उस का आधार क्या है और उसके क्या आंकड़े है कि हम जिस के आधार पर उस का भाव 115,117 रुपये तय करते हैं? इस का सामंजस्य, इस का तारतम्य जरूर बनायें, अगर खेती को आगे ले जाना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से मै यह कहना चाहता हूं कि जो आप के अधिकारी भावों की राय देते हैं, वे आपको यह भी बतायें कि जब गेहूं हमें बीज के रूप में 200-250 रुपये क्विटल पर दिया जाता है, और उसके दिये जाने के बावजूद भी आपके सारे फार्म घाटे में चल रहे हैं, तो फिर हम से 117 रुपये या 115 रुपये क्विंटल पर लेने में हम को कितना लाभ हो सकता है। उस का अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण सुझाव मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देना चाहता हूं। हम जनता पार्टी की गलतियों को न दोहरायें....

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इनके यहां कृषि मजदूर कार्य करते हैं।

श्री राना वीर सिंह : गन्ना और दूसरी पैरिशेबिल कमोडिटीज का भाव यथाशीघ्र तय होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इस के लिये आप एक बोर्ड नियुक्त करें जो कृषकों को राय दे कि कितना उत्पादन होना चाहिये और जितने उत्पादन की राय कृषकों को दी जाय, उतना उत्पादन सरकारी मूल्य पर केन्द्रीय सरकार के लिये खरीदना आवश्यक होना चाहिये, ताकि किसानों को फिर से आलू, प्याज और गन्ने के किसी ग्लट की परेशानी में न पड़ना पड़े।

जहां तक क्षेत्रीय असन्तुलन का प्रश्न है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब कभी कृषि के बारे में बात की जाय तो उसे हरियाणा, पंजाब दूसरे उन्नति शील प्रदेशों की निगाह से न देखा जाय। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है उस के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। न वहां विद्युतीकरण हुआ है, न सड़कें बनी हैं। मैं बहराइच जिले से आता हूं, वहां एक नहर निकली है। वहां जलाशय के पास हमारा जनपद बसा हुआ है, लेकिन उसको एक बूंद पानी भी उस नहर से नहीं मिला है और वह प्यासा ही रहेगा। इस तरह की योजनायें कृषि और सिंचाई दोनों विभागों के समन्वय से बनाई जाय और जिन जनपद के वक्ष-स्थल को खोद कर नहर बाहर आ रही है, उस जनपद को उन का पानी जरूर दिया जाय।

जहां तक नलकूपों का प्रश्न है, हमारे यहां जनता पार्टी के समय मे जो मन्त्री थे उन्होंने ऐसी अनुपयुक्त जगहों पर नल-कूप लगा दिये है, जहां आवश्यकता नहीं थी इसलिये उन ट्यूब वैलों द्वारा पानी की रनिंग-आवरस कम हो गई हैं। इसलिये दूसरे ट्यूबवेल्स नहीं दिये जा सकते। मै कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बहराइच जिले के लिये कोई दूसरा मापदण्ड निर्धारित किया जाय। भिंगा जैसे क्षेत्र में, कांग्रेस के कार्यकाल में, रिग मशीनें भेजी गई थी, लेकिन वहां पर काम पूरा नहीं हुआ और वे ट्यूबवैल अर्धनिर्मित अवस्था में पड़े हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस की तरफ ध्यान दें और तुरन्त रिग मशीनें वहां भेजें जिन से यह अधूरा काम पूरा हो सके और उस सूखे और पहाड़ी क्षेत्र में नलकूपों का काम पूरा हो सके।

[श्री राना बीर सिंह]

आप जो ऋण देते हैं उनको वापस करने की क्षमता का सवाल है। आज केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा आप के पास दौड़ कर आ रहे हैं कि हमारा ऋण माफ किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप उनके ऋणों को माफ न करें, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके पास क्षमता है तो खाद के दामों को अनुदान दे कर सस्ता करे। बड़े और छोटे काश्तकार भिन्न नहीं हैं, काश्तकार तो सब छोटे हैं। आप की तरफ से छोटे काश्तकारों को अनुदान दिया जाय, उन की सहायता की जाय, लेकिन जो काश्तकार 16-17 या 18 एकड़ के हैं, उन को सुविधाओं से वंचित न किया जाय। वे कृषक जो आपका बफर स्टाक भरते हैं, जो दूसरों के लिये गल्ला पैदा करते हैं, उन की उपेक्षा न की जाय।

अन्त में मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारे कृषि मंत्री जी इतना सब कुछ कह रहे हैं वहां यह भी करे कि स्थान-स्थान पर उन्नतिशील पशुओं का भी प्रबन्ध करे, ताकि वे किसानों को मिल सकें। आप जानते हैं कि अशान्ति का कारण केवल गरीबी नहीं है, भूख भी है। यदि भूख नहीं मिट सकी तो मानव मूल्यों के बारे में बात करना निरर्थक होगा।

15 hrs.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Chairman, Sir I, rise to speak on the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture. Sir, this is the biggest Ministry consisting of two i.e. —one is the Rural Re-construction and the other is the Agriculture. I have seen the objectives of the Ministry from the reports given to us. These objectives include everything right from agricultural production to the forestry, fishery, dairy, milk supply—and everything. But I think there is something lacking in its plannnig.

The stereotyped planning of this Ministry alone will not help us to ameliorate the conditions of the people and to remove poverty, from this country or for the betterment of the lot of the agriculturists of this country. Every year we have seen that there is some increased allocation of funds. The Ministry thinks that they have brought about improvement in the Ministry. After three years of Janata and Lok Dal rule, what have they done? They have mismanaged the whole thing. After that it is really very difficult for the new Government to set right everything within a short span of time.

15.02 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE—*in the Chair*].

I feel that the Minister with his background in agriculture and, as an able administrator, should have taken the initiative to set things right. Until and unless we go into the development planning in a proper manner in the Ministry of Agriculture, I do not think we will be able to do justice for the country. This is the only Ministry which can provide more employment for our unemployed youth, Animal Husbandry, Agriculture, Fishery, Foresty—all these—are co-related. By having an accelerated programme in different fields we can bring about increase in the production thereby we will be able to help in the betterment of the lot of the people of this country.

Here, hon. members spoke about many things and they made constructive criticisms also on the working of this Ministry. I would here like to speak about the Union Territory. It may be said that agriculture is the state subject and so the States should take the reponsibility. The Centre is a policy-making body but I say that the Central Government is fully responsible for the development of Union Territories. I would also say that it is the Central Government which alone can do an exemplary work. The Centre can do such types of development work which the State Government should follow. They can also see to it that the Central Government has done something specific for the Union Territories. I come from the Union Territory of Andaman and Nicobar

Islands. What is the position there? There are small isolated territories in that part of the country. There are Andaman and Nicobar islands and the Laksha Dweep islands. There are some union territories where only a single M.P. or at the most, two only represent these territories in this august House? Drought has taken place in the Union Territory of Andaman and Nicobar islands as it has taken place in many places in our country. The Central Team has visited all those areas and they have assessed the damage caused due to droughts. They have tried to understand the problems the people have faced in these areas. No doubt the Central Government has assisted them by all means. But, so far as my territory is concerned, in spite of my repeated request to the Ministry by writing letters, there was not a single officer from the Central Government who went to Andaman and Nicobar Islands to see for themselves the lot of the people there. Of course, the Minister was kind enough to grant us rice for the food for work scheme. But that is not enough. What we require is plough animals; we want free distrbution of seeds, implements. etc. A lot of things is required by us. But nothing has been done. All our cry remained in wilderness.

Now, I would like to say a few words about prices. From mainland we take rice, wheat, etc. and we can sell the rice at Rs. 1.98 per kg. but the local cultivators cannot sell the rice produced by them at more than Rs. 1.72 per kg. I fail to understand the policy of the Ministry of Agriculture in this respect. Sir, the difference between the procurement and distribution price of wheat in the island is about Rs. 40/- per quintal. These matters must be looked into by the hon'ble Minister for such a remote and isolated Union territory. We do not have an Assembly where we could ventilate our grievances. This is the only forum where we can ventilate our grievances.

Now, I would like to take up the point regarding old-age pension to peasants. Throughout the country there is a feeling of insecurity among the poor people. The organised sector and the Government servants have got some sort of security—may not be adequate—but what is the lot of the poor peasant worknig in the fields. It is the peasants who supply food to the country. What is their lot! What is their social security! The Central Government must try to provide old-age pension to agriculturists throughout the country so that they may not feel that they are not benig looked after by the Government.

Sir, I would like to draw the attention of the hon'ble Minister to fisheries. What is the fisheries fishy affair? In the South of our island we have got Bay of Bengal where there is lot of tuna fish. A large number of foreign poachers are coming and taking away our fish but we are not in a position to do anything. Sir, there is Exploratory Fisheries Project. For the last ten years their office is there. What they are doing we do not know because nothing is possible for us to know. In fact, the territory is very much viable for the development of the fishing industry. But nothing has been done.

What have they done during the Janata regime? Sir, I was hearing their speeches. What some of their leaders have done? The big industries, Tata and others, were given trawlers. With the collaboration of foreign countries, they used to catch fish from our waters and sell them in foreign lands. There is no benefit given to our territory. They could not get employment. Therefore, I request the hon. Minister to take this up on a high priority basis and have a Fishing Corporation there. By this, more employment potential can be created there. Fishing can be used as a foreign-exchange earner. At the same time, I want the restart up of the Central Fishing Corporation, Howrah. This was a product of the Congress regime. But this was closed

[Shri Manoranjan Bhakta]

down by the Janata Government. I wrote a number of letters to the hon. Minister and he replied to me. He said, the matter will be placed before the Cabinet. I would like the Minister to expedite this matter so that it could be a viable unit. (*Interruption*) I have to speak about my constituency; this is my Assembly also!

Sir, I now come to the subject of Animal Husbandry. This is one of the important matters connected with Agriculture. In my constituency (Andaman and Nicobar Islands) there is acute shortage of inlet animals. We have to get our cattle from the mainland. Due to climate and atmosphere, these cattle do not survive. What I suggest is that artificial insemination should be taken up speedily. Veterinary services should be provided for all the villages of the country. Until and unless you provide such veterinary services, it is not possible for us to improve the cattle breed or to help the peasantry in agriculture.

In my constituency there are even villages where one has to go 20 miles because there is no proper road. The villager says: 'We don't want anything else, but please give us one veterinary compounder and medicines so that we can attend to our cattle'. This is what the villager wants. So. I request the hon. Minister to look into this and do the needful.

Regarding Forests, I wish to say something. In my constituency 85 per cent of the land area is covered under forests. According to the present statistics, about 23 per cent of the whole land of our country is covered by forests. In 1952, according to the Cabinet decision, it was decided that the country should have 33 per cent of the forest area as a whole. Thereby we can have proper ecological balance and we will be able to save the earth from pollution, soil erosion and many other things. This is one of the important aspects for us to consider. Until and unless we have enough trees and enough forest area in our country, perhaps in the near future, we will not be able to do justice to our people from the health point of view.

In my constituency, very large areas of forests are destroyed in two ways. One is through the Forest Development Corporation and the Forest Department itself and the Factory's coups extracting timbers there. And the other is the encroachment of forests by the landless peasants for getting agricultural land, which is causing a great concern. This is a social evil. Until and unless we check it, there will be a serious disturbance of the entire ecological balance. Therefore, I would like the hon. Minister to amend the Forest Act suitably so that the forest wealth is preserved and well protected. If anybody acts against this Act, he should be given exemplary punishment.

Sir, there are people who have been residing for the last number of years in the forest area and they should be regularised in the forest villages and their responsibility will be to look after the forest so that there is no further encroachment by the people and destroy the forest wealth. Log form timber export should be stopped immediately.

Now, I would like to say a few words about the agricultural research. Research work is being carried out in Andaman and Nicobar Islands by the ICAR. I have seen myself some of the farms in which research work was being carried out by the ICAR. When I wanted to know what they were doing, they said "this is a very important work; you are not supposed to know about it. If you happen to come unofficially, then we might tell you about it." In this connection, I would like to ask the hon. Minister whether MPs are not eligible to know what they are doing and whether any instruction has been issued to them by the Government of India that these things should not be shown to the MPs. I would request the hon. Minister kindly to look into the matter.

Lastly, in Andaman and Nicobar Islands, the forest department has been declared as commercial department. Recently, the railways have announced about the payment of bonus to their employees, the P&T Department also announced that bonus would be given to their employees and the Ordnance Factories also announced that their employees would get bonus. Here in Andaman and Nicobar Islands, the forest department has been declared as a commercial unit and under this there is a Saw Mill called "Chattam Saw Mill" which is one of the biggest saw mills in South-East Asia. The workers working in the mill are covered by the Forest Act and they come under the Industrial Disputes Act. Are they not eligible to bonus? I do not know the reason why they should not be eligible for getting bonus like other workers in Ordnance Factories or Railways or P & T Department. I would request the hon. Minister to do something in this regard, and arrange to grant them bonus as has been done in the case of Railways, P & T Department and Ordnance Factories. Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the budget for Demands for Grants of Agriculture Ministry and I support the same.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Behar): Mr. Chairman, Sir, I cannot support this kulak-oriented, landlord oriented budget for Agriculture Ministry and Rural Reconstruction Ministry. Out of 75 per cent of the total population in the villages, about 72 per cent are agriculturists and according to 1971-72 Census, about 47 millions are agricultural labourers, who form 1/4th of the strength of the work force of our country. There are about 73 millions of share-croppers. There is no ray of hope for about 12 crores of people who are share croppers agricultural labourers toiling masses, who are sacrificing their life just like "Dadhichi". They are producing food for the whole country by their blood and sweat and and we should not forget that 46 per cent of our national income comes from the agriculture. If you ask a village worker, a share-cropper or an agricultural labourer "how do you do", he will say that there is an end for the day, there is an end for the night but there is no end for our misery, Sir, that is the condition of landless agriculturists. Before I deal with share-croppers and agricultural labourers, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Report 1979-80 of the Ministry of Agriculture. On page 54, under Price Policy it is stated as:—

"These terms of reference specify that Agricultural Price Commission would advise the Government on price policy of paddy/rice, wheat, Jowar, maize, ragi, barley, turn, moong, urad, sugarcane, groundnut, soyabean, sunflower seed, rapeseed, mustard, cotton, jute and Tobacco."

I would only request the hon. Minister to kindly add some words after tobacco "...for the interest of mill-owners" thereafter.

The Agricultural Prices Commission is nothing but a white elephant. What is this term 'support price'? It is not at all remunerative to the agriculturists and is not going to improve their condition. Now, what is the support price of the various commodities? For raw jute, the support pirce is Rs. 155 per quintal; for raw cotton, it is Rs. 275 per quintal and for sugarcane, the support price is Rs. 12.5 per quintal provided the recovery is 8.5 per cent. I find no justification for fixation of this support price. Take for example the raw jute. The committee on Public Undertakings in 1978 in their recommendations said that the cost of labour for production of one quintal of jute is Rs. 340 besides 25 per cent additional expenses on agricultuarl implements, manure and other charges. What a gulf of difference is there in between the report of the Public Undertakings Committee and the report of the Agricultural Prices Commission? Who is correct? I know, in West Bengal if the weather is

[Shri Amar Roy Pradhan]

favourable, for production of one quintal of raw jute 36 mandays are needed. Under the Minimum Wages Act, the minimum wage as fixed in West Bengal is Rs. 8.98. On this basis, the labour cost alone for production of one quintal of raw jute comes to Rs. 324. When the minimum cost for production is Rs. 324, you are giving Rs. 155 per quintal to the growers. Should you not fix this support price on the basis of these hard facts? It is nothing but a mockery. When the jute grower sells his raw jute, he gets Rs. 1.50 per kg., but when he goes to the market for purchasing a mill-produced jute bag of one kg. weight, he will have to pay Rs. 5 minimum. In the jute mills the production cost, transportation cost etc. comes to only Rs. 1.50 per kg. and the jute mill owners are thus making a profit of Rs. 2 per kg. This situation is there in the case of sugar and cotton also. I can say boldly that your Agricultural Prices Commission is doing nothing except to serve the interest of big mill owners, like Birla, Dalmia, Goenka and others.

The hon. Members from the ruling party are always blaming the Janta Party for all the ills in the country. They should know that they have been ruling this country for the last thirty years except a short interval. What did they do for the poor people, for the share-croppers and the agricultural labour? The fact is that they did nothing for them. While in the Constitution, we talk of socialism, yet the rural economy still remains in the hands of the feudal monarchy. There are Estate Acquisition Act and Land Reforms Act in every State, but in practice except in West Bengal and Kerala, nothing has been done in other States.

According to Government figures, 68.60 lakh hectares of agriculturable land is available and out of that 45 lakh hectares was declared surplus, but only 15.76 lakh hectares have been distributed so far. The Planning Commission had, however, given a different view that the estimated potential land is about 215 lakh hectares.

In this connection, I would not like to refer to the Mahalanobis Committee Report or the Dandekar Committee Report; I would only like to refer to the Raj Committee Report. The Raj Committee was constituted during the reign of Shrimati Indira Gandhi. According to the Raj Committee Report, 60 per cent of the total cultivable land is in the hands of ten per cent of the agriculturists and ten per cent landlords are enjoying seventy per cent of the total production. And you are speaking of rural reconstruction. You may speak of green revolution but it will help only the landlords.

What a pathetic condition of the agricultural labourers! In 1965 they used to get work for 270 days in a year, in 1976 it came down to 235 days a year and though there are not actual figures availables for 1980, surely it is now round about 200 days in a year. According to the pirce index of 1961, a male agricultural labour used to get Rs. 1.19 in the year 1963-64 and it came down to 88 paise only in 1974-75. I think, today it is not more than 75 paise. There are Minimum Wages Acts in different States. The minimum wages fixed under these Acts vary from Rs. 3.50 to Rs. 8.98 However, except in West Bengal and Kerala, this legislation is only on the Statute Book, it has not been implemented at all. This is the condition of the poor people. The hon. member Shri Manoranjan Bhakta said about the pension of the agriculturists. When our hon. President of Indian Union retires, he will get pension. When a peon of this office retires, he will get pension. Even the Members of Parliament, when they retired after five years, will get pension, but when these poor people, agricultural labourers, share croppers, become old, there is none to look after them; they get nothing.

In this connection, I may refer to the left front Government of the West Bengal. With their limited resources, they have done something for these poor people regarding pension. The share-croppers, the agricultural labourers and the land-holders up to one acre of land, when they will attain the age of 60, he will get pension at the rate of Rs. 60 per month. This system must be introduced in the entire country and the entire cost should be borne by the Central Government.

I would like to warn this Government, particularly the Ministry of Agriculture, do not forget the writings on the wall. In this House, in this air-conditioned House, in this green-carpeted House, you may speak so many things about the Green Revolution about socialism, Jai Kisan, but do not forget these tillers of the soil. They are being exploited for the last 33 years. You did nothing for them. Now they are coming forward. They will make a carpet with your skin and on that skin they will move in a procession with the slogan *"Inklab Zindabad."*

MR. CHAIRMAN: Mr. K. A. Swami, I will call you later on, because the Interpreter is not available. Let him come.

SHRI DIGVIJAY SINH (Surendranagar): Mr. Chairman, Sir, at the outset, let me try and make a suggestion before I deal with more vital issues. The suggestion is that we all know that in this world a country which enjoys a monsoon climate is perhaps a part of the world where the vagaries of nature have to be contended with the greatest care because in this area, you will find diversity of precipitation from one year to another and specially in marginal areas like those where the rain fall, on an average, would be, say, 20" annually. In such areas the vagaries are causing epidemic and in those areas, a cultivator finds himself in a dilemma, because a year may come when he may have the best rain and another year he may have no rain. Look at what happens to my part of the country, that is, Saurashtra where on an average the rainfall has doubled and more than doubled over the last two years causing great hazards and misery; and the next year will be a drought year. In such areas, it is imperative that the Government very seriously consider to have crop insurance; crop insurance is a policy which is remained on the shelves, unimplemented for serveral years. Governments have come and gone but there is no clear decision on this point in this field. Certain progressive States like my State, Gujarat have had a pilot project; may be one or two other States have had a pilot project. But by and large this is an area which needs to be looked into with great care. Cotton is one of the important products of India, particularly in Gujarat, and more so in my constituency. This is a crop which suffers great ups and downs in prices. I know the Cotton Corporation of India is a growing concern and it is pumping money, more money every year, to buy the crop in the field so that middleman is gradually ousted but the amount of money that it has to buy up this cotton is infinitesimal compared to what is required. I know for certain that this year in Gujarat, especially in my area that a cultivator who was producing cotton was producing it at a cost above the cost of sale and therefore every cultivator was making a huge loss. The only solution that I found was to see that more cotton was exported. Government should consider this with gravity. This year something like ten million bales have been produced, 70 lakh bales would have been consumed by the textile mills and only, 7.5 lakh bales have been allowed to be exported. At least 5-6 lakh bales more need to be exported through the C.C.I. whereby the cultivator in the field could realise a better price.

The Food Corporation of India is spread down to practically every

[Shri Digvijay Sinh]

district headquarters. I wish to make the suggestion that they should be brought down to the tehsil, taluk level. There should be storage facility in every block, taluk headquarters and great care should be taken to see that the losses that are incurred in transit and storage, whether it is corruption or spoilage due to rates that eat away a vast percentage of production which is stored, some immediate steps should be taken.

I wish to talk about animal husbandry. We all know that India is a vast sub-continent and it has great diversity and various species of domestic animals, especially, cattle, buffaloes, and a whole lot of animals, right from elephant to angora rabbit and all those various species, compared to international standards are producing neither that much meat nor milk that sustain an animal husbandry industry. We all know that there are certain states, especially Haryana, Punjab and Gujarat where milk production does have a certain semblance of consumption among the general populace. But take the country as a whole, especially big states like U.P. or Bihar or Orissa and find out what is the average daily consumption of milk and milk products. It is dismal; it is scandalous. What has India done in the last so many years since Independence to ameliorate this situation? I think it is scandalous. Much more needs to be done to propagate and to give more impetus to the white revolution whereby the average man in the village consumes more milk and milk products. I wish to talk as an ornithologist about birds. We all know as agriculturists the importance of birds in the agricultural arena. My suggestion is that we should immediately have a national institute whereby various bird species which are on the verge of extinction a lot of them are should be conserved and gene-pools, gene-banks created. The same applies to domestic animals species; a lot of them are on the verge of extinction.

I wish to talk about fisheries. Our colleague from Andamans gave a very vivid description of what is happening in his archipelago. But taking the country as a whole, how much do we know about the marine resources in our territorial waters? No survey has been done. If we want to know about fish migration and shore migration in our territorial waters, we probably have to go to Tokyo to get maps from there to see where the various marine resources lie. Also, can the Government tell us as to how many of the poaching vessels and trawlers from various countries have been arrested and detained for poaching our fish? We have not gone into that at all. Our fish wealth is being poached and over-exploited

Coming to saline land, because of over-drawing and over-exploitation of the ground water, especially along the coastal areas, we find that vast areas of our agrcultural land have become saline wastes, because there is no proper regulation. A national corporation should be created for ameliorating the situation whereby attention could be focussed on the reclamation of the saline land.

Coming to water management, pilot programmes have been funded but hopelessly inadequately. The Land Use Boards which were set up four or six years ago have never met. Land Use Boards are so important for the conservation of the environment and soil of the grassland and general land. But these have been lying indolent for six years. I think something should be done about these very very immediately.

We all want pesticides to conserve our crops from being eaten away by locusts and other pests, but do we konw to what extent toxic substances are injected into the soil and to what extent it is injurious to the health of the society? No survey has been done about this.

Coming to forests, these can be classified under grasslands, village forest programmes and social forestry. All these are probably great employment-oriented agencies. But I can certainly say that the social forestry programme is an eye-wash if you look at it from the point of view of re-generating forests or grasslands or conserving the soil. It is merely an employemnt agency. Because of lack of proper planning in that area, village forest programmes are tom-tommed but actually nothing happens. They are very important and if implemented properly, they can be a fuel substitute to the villagers. We know that after independence, this country has lost 75 per cent of its forests, whether you like it or not. Vast areas of our hills and rocky areas of Himalayas have been laid waste and are barren. The soil has gone into the sea. I do not know how they will be regenerated. All I can say is, there should be remote sensing. There is a remote sensing project, but that has to be implemented immediately so that we know how much we lose and what is to be done in that field.

*SHRI K. A. SWAMI (Visakhapatnam): Mr. Chairman, Sir, many distinguished Members have spoken about agriculture and Rural Reconstruction. I want to bring a few more points to the notice of the hon. Minister.

Sir, at present there is an urgent need for taking up a survey for underground water resources for the cultivation of dry areas. Unfortunately, we are not paying sufficient attention to the underwater resources. A survey should be taken up to locate the underground water. After determining the location we must see that water is brought up for use by tube-wells. The Government must also see to it that proper electrification facilities are provided. Oil engines, electric motors and pumps must also be provided.

There should be a permanent programme to see that every village in dry area is covered under this scheme. Unless we have such a scheme on a permanent footing, we cannot expect more acreage coming under the plough. Only through this scheme can we supply water to small farmers in remote villages in dry area. Ours is an agricultural country. About 75 per cent of the population depend on agriculture. I agree that the Government is spending crores of rupees on projects to bring more and more dry areas under cultivation but such costly constructions will ultimately, have to be supplemented by underground water resources to see the entire dry area in the country coming under the plough. In this regard Punjab stands out as an example. Even small pieces of land are being cultivated there by means of underground water. Other States must follow that example.

In Andhra Pradesh backward areas like Srikakulam, Vizag, Vijayanagaram and East Godavari districts in the State and the country are in constant grip of natural calamities. These areas will experience either drought or heavy rain year after year. For the past 20 years there has not been even a single harvest, with the result that many farmers are leaving their farms and villages and settling down in nearby towns. Sir, a person who owns a pan-shop or works as dock labourer is able to see his son becoming a doctor, an engineer or an I.A.S. officer. But, the poor farmer who sticks to his land in his village is not able to provide even primary education to his children even though he owns 25 acres of land. I need not stress upon the difficulties of these dry land farmers any further for much has already been said about it.

*The original speech was delivered in Telugu.

[Shri K. A. Swami]

Research must be carried out to find how much investment is needed on an acre of land for cultivation. The minimum price must be decided on that basis. A minimum support price is needed, otherwise it may lead to a fall in production. At present, sugar cane growers are not getting a remunerative price for their cane. They are not able to get back even their investments. Factory owners are purchasing the cane at a price which is much below the price fixed by the Government.

Sir, nationalised banks are not extending credit facilities to all the poor farmers in villages. They are not extending the credit facilities even in their adopted villages. The farmers must be supplied with pass books on a permanent basis and they must get the required credit on the production of such pass books. Even the policies of the Reserve Bank of India are not at all serving the interests of the farmers. On the contrary they are harming the farmers. In this connection, I request the hon. Minister to take this matter very seriously and set things right as early as possible, and see that the farmers get credit facilities even in remotest villages

One more important point to which I want to draw the attention of the hon. Minister is the Crop Insurance Scheme. The scheme is already in operation in many countries. Our country and our farmers have already suffered very much. I do not know why the Government is hesitating to adopt this scheme. I hope the hon. Minister will not waste any further time to help our farmers by implementing this scheme. It will give our farmers the support they need in their hour of distress.

The marketing facilities available to the farmer are too inadequate. The storage facilities are also very much inadequate. Godowns must be constructed in every village to store its produce. If it is not possible, the Government should hire godowns from private owners.

We have the Jute Corporation of India to serve the needs of the growers and the industry. But instead of purchasing the jute directly from the growers, it is at present purchasing it from the middle men. These middle men purchase the jute from the growers at a low price and profit by selling it at enhanced prices to the J.C.I. There are huge stocks lying with the farmers even now. I request the hon. Minister to see that these middle men and agents of mill owners should be eliminated and the growers should get a remunerative price for their produce.

At present the forests are being continuously destroyed on various pretexts and replantation programme is not being carried out. Though we have a Forest Department, it is not helping the growth of forests. Afforestation programme must therefore, be taken up seriously and the entire waste land in the country must be converted into a green land. In this regard Orissa has achieved some success and other States shou'd follow this example.

I hope the hon. Minister will consider my points. With these words Sir, I support the demands.

MR. CHAIRMAN: Before I call the next speaker I would request hon. Members not to come near the Chair. If they have anything to communicate, they should only send slips to the Chair.

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : माननीय सभापति जी, दो दिन से कृषि की अनुदान मांगों पर बहस चल रही है और इधर उधर के बैठने वाले सभी सदस्यों ने यह कहा है कि कृषि उत्पादन का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता है, कृषि का सही दाम उन को नहीं दिया जाता है। यह आज से नहीं बल्कि पिछले 34 सालों से रोना चल रहा है और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं उन को उचित मूल्य दिया जाता है। बार बार यह कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार भी आई और उस ने यह भी नहीं किया कि किसानों को उचित मूल्य देती लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नहीं दे

पाई इसलिए ढाई साल में वह खत्म हो गई लेकिन आप तो 33 साल से बैठे हैं, आपने क्यों नहीं उन को उचित मूल्य दिया.....(व्यवधान)... सरकार की यह हालत है कि किसानों को उन की उपज का सही मूल्य नहीं दिया जाता जबकि फक्टरी वालों की उन के माल के दाम सारे मिल जाते हैं । मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं । हमारे मिर्जापुर में हिन्डालको फैक्टरी है, जिस को 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है जबकि किसानों को 27 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है । मैं यह पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या केवल 20 फीसदी आदमियों को ही आजादी मिली है और 80 फीसदी आदमी आज भी गुलाम हैं । आप बिरला को 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं और किसानों को 27 पैसे प्रति यूनिट । जब लागत खर्च 13 पैसे आता है, तो 11 पैसे प्रति यूनिट आप उन को देते हैं और पहले जब ढाई पैसे लागत खर्च आता था तो बिरला को दो पैसे प्रति यूनिट बिजली देते थे । हिन्डालको को आप सस्ती बिजली देते हैं और किसानों को महंगी बिजली देते हैं । यह हालत इस सरकार की है और यह सरकार सरमायेदारों की ही वफादार रही है और किसानों और गावों के लोगों को मिटाना चाहती है । जितनी, बिजली देश में बनती है, उस का 60 फीसदी उद्योगों में चला जाता है और किसानों को केवल 6 फीसदी बिजली दी जाती है जबकि सारा खर्चा किसानों पर, एग्रीकल्चर पर डाल दिया जाता है । 8 फीसदी बिजली रेलों को दी जाती है और बाकी जो बिजली बचती है वह दिल्ली और पूना जैसे बड़े बड़े शहरों को जगमगा रही है जबकि किसानों के खेत सूख रहे हैं । इंडस्ट्री में केवल 5 फीसदी लोग काम करते हैं और खेती में 80 फीसदी काम करते हैं लेकिन इतना होने पर भी किसानों को कुल 1281 करोड़ रुपए दिए गये हैं, जिस में केवल 18 करोड़ रुपए किसानों को जाएगा और बाकी जो रुपया है वह कृषि में लगे हुए लोगों की तन्खवाहों में चला जाएगा । इस तरह से किसानों के बजट का 70 फीसदी पैसा तन्खवाह में चला जाता है । इस के अलावा आप यह देखें कि इंडस्ट्री में 5 फीसदी आदमी काम करता है, तो उस को 350 करोड़ रुपए दिये गये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पिछले 34 सालों में कोशिश इस बात की ही हुई है कि बड़े बड़े शहरों की तरफ देखा जाए और गावों में रहने वालों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है । गांवों में 5 फुट का रास्ता नहीं है जबकि इन शहरों में 500, 500 फुट का रास्ता बना हुआ है । आज देश में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि जो कोई वस्तु बनाने वाला है, वह अपनी चीज के भाव तय करता है लेकिन किसान ही ऐसा अभागा है, जो पैदा खुद करता है लेकिन एअर कंडीशन्ड कमरों में बैठ कर दिल्ली में 3 आदमी उस के भाव तय कर देते हैं और वे ऐसे आदमी हैं जिन के बाप-दादा को भी यह पता नहीं था कि बाजरा में और ज्वार में बाल क्या होती है । इस को उन को पता नहीं है ।

मैं आप को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । एक एकड़ में किसान का कितना पैसा खर्च होता है, उस के आंकड़े मैं आप को देता हूं । बीज 40 किलो, 200 रुपए का, खाद 200 रुपए, यूरिया, एक कट्टा 130 रुपए का, डी० ए० फी० खाद 170 रुपए, जुताई, बुआई, में 315 रुपए, निकाई, गुड़ाई 150 रुपए, पौधा संरक्षण तथा दवाई 100 रुपए, सिंचाई में 350 रुपए, कटाई 100 रुपए ढुलाई 40 रुपए, मढाई 50 रुपए, मार्केटिंग के लिए ले जाना 25 रुपए जमीन की कीमत 750 रुपए, जमीन का रख-रखाव 100 रुपए और एक मजदूर की तन्खवाह 300 रुपए । इस तरह से एक एकड़ पर कुल लागत 2,980 रुपए आती है । एक एकड़ में 6 क्विन्टल गल्ला होता है । उसकी कीमत आप किसान को सात सौ रुपए देते हैं । उसका जो खर्च आता है उसके मैंने अभी आपको आंकड़े बताये हैं । इसके बारे में आप आयोग से मालूम कीजिए या कोई कमीशन बिठाइए । अगर खेती को उद्योग में ले लिया जाए तो जैसे उद्योगों में सारा खर्चा लगा कर दाम जोड़ा जाता है उस तरह से : इस एक क्विन्टल गल्ले का दाम एक हजार रुपए से कम नहीं बैठेगा ।

एक हमारे यहां सोयल कंजवशन डिपार्टमेंट है । इस में सिवाय एक फला और फावड़े के कुछ भी नहीं है और उसका खर्चा अरबों रुपए का है । मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि इस सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को खत्म किया जाए और हर कमिश्नरी को पांच बड़े बुल्डोजर दे दिए जाएं । जिनके आगे लेवलर लगता हैं, ऐसे बुल्डोजर दे दिए जाएं जो कि चम्बल जमुना, गंगा, क्वारी, सिरसा और सेंगर नदियों की 50 लाख हेक्टेअर जमीन को एक सा कर दें और फिर वह जमीन गरीब आदमियों और भूमिहीनों में आप बांट दें ।

एक लघु सिंचाई विभाग कहलाता है । इसकी हालत यह हो रही है कि उसके पास एक मूंज की रस्सी और चार फुट का एक पाइप है । जब वह बोर करता है, अगर पत्थर और कंकड़ आ जाए तो वह बोर नहीं कर सकता । इसके लिए मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि लघु सिंचाई को दो से चार इंच तक की रिंग मशीन दी जाएं जिनसे तमाम किसान प्राइवेट बोर कर सकें । आपके ट्यूब वाले तो आठ से बारह इंच के रिगों से बोर करते हैं । लेकिन इनसे किसान प्राइवेट बोर नहीं कर सकता है ।

उत्तर प्रदेश में झलेसर, देहरादून और आइजट-नगर में रिसर्च फार्म हैं । पन्तनगर, कानपुर और फैजाबाद में कृषि यूनिवर्सिटियां हैं । ये सब की सब बिजनेस सेन्टर बन गयी हैं । ये

[चौधरी भुलतान सिंह]

किसान से सवा रुपए में ले कर पांच रुपए किलो में बीज बेचती हैं फिर भी इनमें अरबों रुपये का नुकसान होता है । मैं सुझाव दूंगा कि इन सब को खत्म कर दिया जाय। न रिसर्च फार्म की जरूरत है और न रिसर्च यूनिवर्सिटी की जरूरत है । इन पर खर्च होने वाले पैसे से चार-पांच गांवों के बीच में दो-तीन एकड़ के रिसर्च फार्म खोल दिये जाएं जहां गांव के आदमी जा कर देखें और सीखें । वहीं से वे बीज लें ।

शहरों में भण्डार पर भण्डार बनाये जा रहे हैं । ये यू० पी० से गल्ला मद्रास भेजते हैं और मद्रास से दिल्ली भेजते हैं । पहले बनिया एक रुपए क्विन्टल के मुनाफे पर गल्ला बेचा करता था । ये एफ० सी० आई० वाले 25 रुपए क्विन्टल ले रहे हैं । गांवों में पुराने जमींदारों की पुरानी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं । वे आपको सस्ते किराये पर मिल सकती हैं । आप वहीं की वहीं गल्ला खरीद कर उनमें रख सकते हैं और वहीं को वहीं गल्ला गरीबों में बांट सकते हैं ।

हरियाणा में विश्व बैंक योजना चल रही है। उस में ज्यादातर दिल्ली और दूसरे बड़े बड़े शहरों के बी० एस० सी०, एम० एस० सी० साढे सात सौ से तेरह सौ रुपए तक की तंख्वाह पर भर दिये गये हैं जिनको यह तक पता नहीं है पौध के ऊपर बाल लगती है या बाल के ऊपर पौध लगती है । ये गांवों में कभी नहीं जाते सिर्फ अफसरों को बियर पिला कर तंख्वाहें लेने के लिए जाते हैं । मेरा आपको सुझाव है कि कृषि विभाग के अन्दर चपड़ासी से ले कर मंत्री तक सभी किसान के लड़के होने चाहिएं क्योंकि उन्हें प्रेक्टिकल ज्ञान तो होता ही है, थियोरिटिकल ज्ञान उन्होंने पढ़ कर लिया होता है। उनसे सही काम हो सकता है ।

हमें यह उम्मीद थी कि कृषि में आप सिंचाई, बिजली, खाद और पानी विभाग भी देंगे और रुपए भी देंगे लेकिन आपने उस से सिंचाई विभाग निकाल लिया और दिया कुछ नहीं । मेरा सुझाव है कि कृषि के काम आने वाली वस्तुएं जितनी भी हैं, वे सभी एक मंत्रालय के नीचे होनी चाहिएं । चाहे ये प्रदेश में हों या देश में हों । आज दिक्कत यह हो रही है कि स्टेट छोटी और कारिन्दा ज्यादा । अगर आपको मंत्री बढ़ाने ही हैं तो आप बेशक घोड़े का, लकड़ी का, सफाई का विभाग खोल दीजिए । और उनमें मंत्रियों को रख दीजिए लेकिन यह मंत्रालय एक ही होना चाहिए, उसमें चाहे राज्य मंत्री कितने ही हों । यह मंत्रालय चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो ।

यह कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण डिमांड्स पर मुझे बोलने का समय दिया । निश्चित तौर से बहुत से साथियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन आज देश अपने कृषि मंत्रालय का आभारी रहेगा । कुछ साथी चर्चा करते हैं कि 30, 35 सालों में कोई तरक्की नहीं हुई, मैं कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी बड़ी तूफानी बाढ़ों के बावजूद कृषि का उत्पादन हिन्दुस्तान में बढ़ा है । मैं खास तौर से अपने कृषि वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रयास से हर क्षेत्र में खोज हुई और आज हमारा हिन्दुस्तान भी दूसरे देशों के सामने अपना सिर ऊंचा कर के खड़ा होता है । अगर मैं आज उनको धन्यवाद नहीं देता, तो अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाऊंगा ।

मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, जिनके बारे में हमारे दूसरे सदस्य बोल चुके हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कृषि की तरक्की करनी है तो निश्चित तौर से जो छोटे किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, आदिवासी, गिरिजन, हरिजन हैं, और देश के तामम वह क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, ड्राइवल हैं, जब तक कृषि के विकास का काम उनके बीच में नहीं होगा, तब तक निश्चित तौर से हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा । मुझे खुशी है कि कृषि विभाग ने इनकी तरक्की के लिए बहुत सी योजनायें बनाई हैं ।

एक योजना डी० पी० ए० पी० है, ड्राउट-प्रोन एरिया प्राजेक्ट इसके तहत तमाम हिन्दुस्तान में सूखे के लिए 78 जिले छांटे गये थे, लेकिन जो सूखे की राहत के लिए तेजी से कार्यक्रम चलना चाहिए था, वह नहीं चला । एग्रीकल्चर कमीशन में एक स्टडी टीम बनी थी श्री वी० शवरमण के नेतृत्व में । उन्होंने हिन्दुस्तान का दौरा करने के बाद बहुत से सुझाव दिये थे गांवों का विकास करने के लिए । उसके लिए 38 गांव चुने गये थे । बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में । उनमें से उत्तर प्रदेश में 5, बिहार में 23, उड़ीसा में 6 और तमिलनाडु में 4 थे । इनमें 5 गांव उत्तर प्रदेश के थे जो मेरी कांस्टीटुएन्सी में पड़ते थे । इसके अलावा 100 गांव और लिए गए थे । जिनमें डिमांस्ट्रेशन के तौर पर कृषि की तरक्की की बात करनी थी । उसके जो रिजल्ट आये हैं वे अच्छे हैं और उत्साह-वर्द्धक हैं । हमारे यहां एक बनवासी शिव आश्रम है जो कि रिप्यूटेड सोशल आर्गेनाइजेशन है । यह काम उसको सौंपा गया था । इन 100 गांवों में जो काम हुआ उसका मल्यांकन एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन बम्बई ने किया है । मैं बताना चाहता हूं कि 160 रुपए जिनकी पर-कैपिटा इनकम थी गांव की, उनकी 3 साल में 272 हो गई । शिक्षा में 14 परसेंट से 27 परसेंट

लिटेरेसी हो गई और 35 परसेंट लोग पावर्टी लाइन से उपर आ गये । इस तरह की 4, 5 चीजें हैं। हैल्थ में 98 प्रतिशत सफलता रही और ऋण-मुक्ति शत-प्रतिशत सफल रही । इस प्रकार से इनकी जो फाइन्डिंग्ज हैं, वह बहुत उत्साहवर्द्धक हैं ।

मैं कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि जहां भी ऐसे क्षेत्र हैं, वहां होल विलेज डेवलपमैंट कार्यक्रम को विस्तार से बढ़ाया जाये और एक कम्प्रीहैंसिव विस्तृत प्रोग्राम हो जिसमें कृषि ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाएं और अनेक प्रकार के कम्युनिटी डैवलपमेंट के समग्र विकास के कार्यक्रम हों । मैं ने अभी कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री से कहा था कि जो उपलब्धियां हुई है, उनके आधार पर एक सैमिनार आयोजित किया जाये । उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ।

16.00 hrs.

छोटे काश्तकारों और सीमान्त कृषकों को--ढाई एकड़ तक वाले काश्तकारों को --33 परसेंट सहायता दी जाती है । मैं चाहता हूं कि उन्हें 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाये ।

उत्तर प्रदेश में तीन इलाका में पिछड़े हुए जिले हैं : पूर्वी उत्तर प्रदेश मे 15 जिले, बुंदेलखंड में 5 जिले और 8 पहाड़ी जिले । उनकी हालत बहुत खराब है । उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए । समुचित योजनाओं को कार्यान्वित कर के उन्हें ड्राउट-प्रूफ बनाया जाये । सूखे से छुटकारा पाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और एक्सपर्ट्स कोई स्कीम बनाये और उसके रिजल्ट सारे हिन्दुस्तान पर लागू हों ।

हिन्दुस्तान भर में 5028 ब्लाक है । लेकिन दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश को उनका हिस्सा नहीं मिला है । मैं मांग करना चाहता हूं कि कृषि सेवा केंद्रों का विस्तार किया जाये, जिनके अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था और आर्थिक तथा तकनीकी सहायता की जाती है । ये सारे कार्यक्रम सैंट्रली-स्पांसर्ड थे । पिछले वर्ष जनता पार्टी के रेजीम में इन कार्यक्रमों को प्रदेशों को ट्रांसफर कर दिया गया । नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में यह निर्णय ले लिया गया । इससे इमबैलेंसिज और बढ़ गये हैं । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर पुनर्विचार करे । जो योजना केन्द्र द्वारा बनाई जाती है, जिसके के लिए पैसा केन्द्र द्वारा दिया जाता है, उसके सम्बन्ध में जो गाइडलाइन्ज दी जाती हैं, राज्य उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं ।

बहुत सी स्टेट्स भूमि-सुधार के कार्यक्रमों में बहुत पिछड़ी हुई हैं । गरीबों को जो जमीन एलाट हुई है, उसपर उनको कब्जा नहीं मिला है । सैंट्रल गवर्नमेंट से यह आदेश जाना चाहिए कि उन लोगों को जमीन का कब्जा दिलाया जाये । भयावह बाढ़ से आये-दिन परेशानियां होती हैं । यदि किसी गरीब किसान का घर गिर जाता है, तो उसे 200 रुपए की सहायता दी जाती है । यह रकम बहुत कम है । अगर किसी किसान का घर गिर जाये, तो उसे कम से कम 1,000 रुपए मिलने चाहिएं ।

मैं सरकार और कृषि मंत्रालय का बहुत आभारी हूं कि इस भंयकर और अप्रत्याशित सूखे में --भारत के इतिहास में ऐसा सूखा पहले कभी नहीं पड़ा है--उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि एक भी इन्सान भूख से नहीं मरने पाया । इससे हमारा मस्तक ऊंचा हुआ है । हमने देखा था कि बंगाल के अकाल में लाखों आदमी मौत के घाट उतर गये थे । आज जो व्यवस्था की गई है, वह हमारे लिए गौरव का विषय है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और कृषि मंत्रालय धन्यवाद के पात्र हैं ।

पशुओं को सूखे से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उनके चारे के बारे में जो गाइडलाइन्ज भेजी है, कुछ स्टेट्स उन पर अमल नहीं कर सकी है । मिर्जापुर में 30 परसेंट पशु मर गये । मैं मांग करना चाहता हूं--मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री आ गये हैं, मैं ने उन्हें पत्र भी लिखा है--कि जिन किसानों के जानवर मर गये हैं, उन्हें सबसिडी दी जाये, ताकि वे कृषि का काम कर सकें ।

सूखे में रिग मशीनों ने बहुत काम किया है, लेकिन उनकी संख्या अपर्याप्त है । उत्तर प्रदेश सरकार ने रिग मशीनें मांगी हैं ।

श्री विरेंद्र सिंह राव : वहां भेजी हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका : लेकिन वे काफी नहीं हैं । और रिग मशीनें दी जायें, ताकि पानी के बारे में स्थायी हल हो सके ।

सरकार ने किसानों के लिए जो योजनायें चलाई है--एस एफ डी ए, डी पी ए पी, एम एफ डी ए, आदि--उनका विस्तार किया जाना चाहिए । आदिवासियों के लिये ट्राइबल पायलट प्राजेक्ट चलाये गये हैं, जिन्हें टी डी ए प्राजेक्ट कहा जाता है । सरकार ने कुछ ब्लाकों को चुना है । इससे काम नहीं चलने वाला है । हिन्दुस्तान भर के सारे ट्राइबल एरिया को उसमें शामिल करना चाहिए । हरिजन और आदिवासी देश की आबादी का 25 प्रतिशत हैं । उनके जो विकास के लिये कार्यक्रम बनाने चाहिएं ।

जैसा कि श्री मिर्धा ने कहा है, बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह निश्चित रूप से कम है । उसको बढ़ाना चाहिए । सभी

[श्री राम प्यारे पनिका]

राज्यों को निर्देश दिया जाये कि दस वर्ष तक जंगल न काटे जायें । राजा साहब बैठे हैं । वह उत्तर प्रदेश में फारेस्ट मिनिस्टर थे । उन्होंने कुछ इलाकों में दस वर्ष तक जंगल काटना रोक दिया था । आज आवश्यकता यह है कि जंगल को कटने से आप रोकें । उन का ठेका वगैरह न दिया जाये । स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर स्टेट की सरकारें अनाप शनाप उन की नीलामी कर रही हैं । आप इंडियन फारेस्ट एक्ट में कुछ ऐसा प्राविधान कीजिए कि आप को अधिकार मिल जाय कि जब तक आप अधिकार न दें तब क जंगल वह न काट सकें ।

जानवरों के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था पूरी कीजिए । जगह जगह उन के रिसर्च सैंटर्स को बढ़ाइए ।

इसी प्रकार से जैसे इंडस्ट्री के लिए आप बिजली में छूट देते हैं ऐसे ही डीजल वगैरह में किसानों के लिए सब्सिडी दीजिए । यही नहीं, सब जगह डीजल के पम्प्स नहीं लगे हैं । जहां जरूरत हो वहां पम्प्स की व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI LAKSHMAN MALLICK (Jagatsinghpur): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.

The agricultural production has a great importance in our country. Apart from the need for food, this sector employs the bulk of our labour force and their wellbeing depends on a high level of productivity. During the year 1978-79, foodgrains production has reached a record level of 131.37 millions tonnes. We should take note of certain important facts for such a record.

Firstly, this figure includes the production of both cereals and pulses. But production of pulses has hardly changed. It has fallen below that of the year 1975-76. Practically, pulses have disappeared from the diet of the poor people here. The lower and middle class people are not able to purchase these for their diet. A massive research effort has to be mounted for augmenting the pulses production in unirrigated areas.

Secondly, the overall production figures do not bring out correctly the regional situations. Out of a total increase of 4.76 million tonnes in cereal production in 1978-79 over 1977-78, 3.23 million tonnes are on account of wheat. The area of rice-growing is comparatively larger than that of the area under wheat. There are many reasons probably for less production of rice. The natural calamities also played a part for less production. The wheat production has been increased more significantly than rice production. The yield per unit area in many of the rice producing areas is very low. Our food situation will never be comfortable. The farmers of rice-growing areas will continue to suffer unless this production disparity is corrected. One of the major reasons for the stagnation in rice production is due to poor irrigation support. Wherever the irrigation facilities are available the farmers have adopted the improved practices and have increased their consumption of inputs and achieved a satisfactory level of production. Unfortunately, greater part of this area continues to depend on rains. To correct such imbalances between rice growing area and wheat area a policy decision has to be taken that the Centre will assist the States in execution of irrigation schemes.

Sir, for our food production we depend on imported fertilisers. Fertiliser consumption has improved remarkably from 2.57 million tonnes in 1974-75 to 5.11 million tonnes in 1978-79. I hope there is no likelihood that this import of fertilisers will stop in the near future. It is revealed from the Report of the Ministry that some important fertilisers are not available and the prices in the international

market have been rising and the suppliers do not want to honour the contractual commitments. We have to take note of these facts. We should also step-up domestic production in order to make the country self-sufficient in this sector. This needs for a perspective plan for setting up fertiliser plants. Such a plan should be drawn up quickly and implemented.

Sir, the recent increase in fertiliser price has made it imperative that the farmer should get a fair price for his produce. In the absence fair price shops the production level cannot be maintained. A large number of jute farmers in Orissa do not get a fair price. They are very often forced to part with their produce at a throw-away price. Procurement of jute at fair price should be organised.

Sir, the rural employment situation is alarming. There is clear evidence about increasing of unemployment and under-employment in rural sectors. Unfortunately, there is no single thrust in our programmes of rural development. A variety of programmes with practically same programme contents are being implemented. At the State level these programmes are some times controlled by different departments with the result that the schemes work at cross-purposes. So, it creates confusion alround. There is no reason why all such schemes meant for betterment of small and marginal farmers and landless labourers cannot be blended into a single scheme. The Finance Minister in his budget speech referred to a National scheme of rural employment. We hope this scheme will not be yet another routine scheme and all schemes with identical contents but operating under different labels will be blended together. We do not see adequate thought being given for organising a viable machinery for rural development.

The blocks installed in the 1950s, have fallen into disuse and are now without any viable programme. Keeping in view the need to provide more important services at one place to the Rural community block pattern was originally designed. This was a novel experiment. But, before it could be fully established, it was called off. As such, at present, we have no agency to implement the rural development programme. If this situation continues, the bulk of the outlay will remain unspent and the benefits meant for the people will not reach them. So, I would suggest that serious thought should be given to reconstituting the block machinery so that various disciplines connected with rural development work are integrated into a singly administered administrative apparatus.

Then, Sir, my last point is this. The Railways do not serve equally all parts of the country. For example, in Orissa, there are many districts, which are not served by the Railways. The price of fertilizer is based on f.o.r. destination rail-head. There is very little margin of profit. Therefore transport of fertilizer from the rail head to the interior area has become uneconomical.

As a result, much of the interior areas are denied the advantage of getting fertilizer at reasonable price. Many State Government like Orissa have been urging the Government of India to declare the block headquarters as national rail-read, so that the fertilizer can be transported by road from nearest railhead to the block headquarters, which would be destination point for f.o.r. destination price. Without this facility, the consumption of fertilizers in the backward States like Orissa is not likely to improve much. So, Government should declare block headquarters as rail-head.

With these words I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN: Shri L. S. Tur...

श्री लहना सिंह तुर (तरन तारन) (*spoke a few words in Punjabi*).

MR. CHAIRMAN: Either you speak in Hindi or you speak in English. If you want to speak in Punjabi, you may speak later. You have not given any previous notice.

श्री लहना सिंह तुर : पंजाबी ओखी जबान नहीं है, सोखी जबान है ।

सभापति महोदय : आप हिन्दी में बोलिए क्योंकि अभी इन्टरप्रीटर नहीं हैं और नहीं तो बाद में बोलिए ।

श्री लहना सिंह तुर :: मैं बाद में बोल लूंगा, लेकिन बोलूंगा पंजाबी में ।

श्री कुम्भाराम आर्य (सीकर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और जिस के लिये सरकारी प्रोत्साहन की बात कही जा रही है, वह "लम्बा हेला, ओछी बीख" के सिवा कुछ भी नही है । मैं आप के द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि किसानों के साथ बड़ा पक्षपात होता है, उन के साथ बड़ा अन-जस्टिस होता है और इतना कठोर सौतेला व्यवहार होता है कि जिस को कोई सहन नही कर सकता । यह किसान ही ऐसा है जो इन सारी बातों को सहन करता है ।

मैं इस वक्त गन्ने और चीनी की बात कहता हूं । चीनी पैदा करने में किसान को भी काम करना पड़ता है और उद्योगपति को भी काम करना पड़ता है । उद्योगपति को अपनी मिल चलानी पड़ती है और किसान को गन्ना पैदा करने के लिये अपने खेतों में काम करना पड़ता है । लेकिन इन दोनो के साथ सरकार का क्या व्यवहार है ? इसकी तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । चीनी मिल के लिये कानून बनाया जाता है, एरिया डिमार्केट किया जाता है । उस एरिये में पैदा होने वाला गन्ना किसी दूसरी जगह नही बेचा जा सकता अगर कोई बेचता है तो उस को सजा मिलती है । दूसरी तरफ किसान को मजबूर किया जाता है कि वह उसी मिल को गन्ना बेचेगा, दूसरी जगह नहीं बेचेगा । नतीजा यह होता है कि मिल-मालिक उस को उस के गन्ने का पैसा भी नही देता, उधार की पर्ची पकड़ा देते हैं उस उधार की पर्ची की हालत यह है कि उस का पेटेन्ट पांच-पांच साल तक नही होता, करोड़ों रुपये चीनी मिल मालिकों के पास किसानों के पड़े हैं, किसान को रकम का ब्याज भी नही मिलता । इस सरकार से कोई पूछे कि इस तरह का दुर्व्यवहार किसान के साथ करने में सरकार को क्या लाभ है ? किसान को बरबाद करने के लिये इस तरह का कार्य सरकार क्यों कर रही है ? उस को इस में क्या मिल रहा है ? मेरा ख्याल है कि इसमें इस के सिवा कुछ नही—

सतहीना सरदार मतहीना राखे मिनख

अस अन्धे असवार राम रुखालो राजिया ।

इन को कुछ भी पता नहीं है कि किसान के साथ क्या हो रहा है, उस पर क्या गुज़र रही है ।... ....(व्यवधान)....... मैं भी किसान का ही बेटा हूं, किसी बानिये का छोरा नहीं हूं

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान गन्ना बोता है, उस गन्ने को सरकार पानी देती है । चीनी मिल वालों को चीनी बनाने के लिये, मिल चलाने के लिये बिजली देती है । बिजली के पैसे में कोई गड़बड़ नहीं । लेकिन खेती में जो पानी लगता है, अगर किसान ने उससे गन्ना पैदा कर लिया तो पानी की दर ज्यादा ली जाती है । जो दर गेहूं के लिये या बाजरे के लिये है, गन्ने के लिये वह दर नही । गन्ने के लिये ज्यादा दर चार्ज की जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि किसान के साथ यह पक्षपात क्यों ? क्या आप ने पानी में कोई हींग डाल दी है या फिटकरी डाल दी है, क्या कर दिया है जो गन्ने के लिये पानी लगे उस की कीमत ज्यादा चार्ज करेंगे और गेहूं या बाजरा में जो पानी लगेगा तो उस की कीमत कम वसूल करेंगे ? इस तरह का व्यवहार मिल-मालिकों के साथ क्यों नही किया जाता अगर वह चीनी पैदा करेगा तो उस से बिजली का ज्यादा पैसा लेंगे, अगर खण्डसारी पैदा करेगा तो कम पैसा लेंगे ? इस तरह का व्यवहार मैंने "राम और राज" के घर में कहीं नहीं देखा, सिवाय इस कांग्रेस राज के । राम किसान को दो नजर से नहीं देखता, राज को भी दो नजरों से देखने का अधिकार नहीं है कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कृषि मंत्री आप उस राव तुला राम की संतान हैं, जिसने दिल्ली के सम्मुख कभी सिर नहीं झुकाया था और आपने हरियाणा का गुजाया था--

राव आया, भाव आया

राव गया, भाव गया ।

इस वक्त आप हरियाणा में नहीं हैं, दिल्ली हाथ लग गई है, कर दे दो हाथ । क्या दिक्कत है ? किसान की भलाई करने में अगर यहां से चले जाना पड़े तो राज भरोसा करें किसान वापस ले आये, एक बार किसानों का भला कर के दिखला दे । किसान की दुहाई सब देते हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिये कोई तैयार नहीं है ।

मैं आप को एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं । हम बड़े ऋण देते हैं, ऋणों से किसानों का भला करते हैं । आप ऋण से भला भी करते हो और किसानो को बरबाद भी करते हो । जो छोटा किसान है, वह अपने खेत में कूआं बनाने के लिये ऋण लेगा, मशीन लगवायेगा, लेकिन पैदावार शुरू नहीं होगी, उस के पहले ही पहली किश्त और दूसरी किश्त ड्यू हो जायगी । वह किश्त अदा नहीं कर सका तो सरकार उसकी मशीन

को निकालने जाएगी, निलाम कर देगी । मशीन को निलाम कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन मिनिमम चार्ज के नाम पर बिजली का बिल फिर भी भेज देंगे लोगों से साल-साल भर की बिजली की वसूली की जाती है । यह कोई अकल का काम है ? यह मूर्खों का काम है, बेईमानी का काम है । इस पर थोड़ी नजर डालिये, राव साहब ।

एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं जिस किसान ने अपनी जमीन के डेवलपमेंट के लिए ऋण लिया कुंआ बनाया और उस कुंए में पत्थर निकल गये या पानी खारी निकला आया, अथवा उस की फसल को टिड्डी ने खा लिया या कोई और बीमारी आ कर लग गई, फसल नष्ट हो गई बस फिर क्या था, सरकार आई और उस के खेत को निलाम कर दिया । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरहबानी कर के गरीब किसान को उजाड़ो मत । किसी को बसा नहीं सकते तो मत बसाओ । लेकिन किसान की जमीन निलाम करते हो यह किसानों के साथ सब से बड़ी इनजस्टिस है । इस को रोकना चाहिए । एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम किसानों की उन्नति के लिए पैसे देते है और उस पैसे को अगर किसान अदा नहीं कर सकता है उस की भूमि की नीलाम करके उसको भूमिहीन बना देते हो और फिर कहते हो कि भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है । इसमें दोष किसका ? अगर आप रहे और आप के लोन बढ़ते रहे और उनकी वसूली आप इस तरह से करते रहे, तो किसानों की संख्या घटेगी और मजदूरों की संख्या बढ़ेगी । यह आप के काम करने के तरीके की मेहरबानी है । मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों की भूमि को निलाम होने से रोक देना चाहिए और इस की वजह से अगर सरकार को नुकसान होता है, तो उस को भुगत लेना चाहिए । ऐसा करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है किसान इस हैसियत में नहीं है कि वह सरकार से लड़ सके । अगर किसान इस हैसियत में होता, तो आज से बहुत पहले ही वह सरकार से लड़ कर अपना हक प्राप्त कर लेता।

सभापति जी, आप घंटी न बजाएं मैं बोलूंगा। आप मार्शल से निकलवा सकते हैं । मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं अपने दुख दर्द कहने के लिए आया हूं । घंटी बजाने से मेरा दिमाग बिगड़ जाता है, इसलिए इस को मत बजाइए ।

समापति महोदय : हम नहीं चाहते लेकिन हमें घंटी बजानी ही पड़ती है ।

श्री कुम्भा राम आर्य : मैं एक बात और बताना चाहता हूं । सरकार ने जितने बिजली बोर्ड बना रखे हैं, हर एक बिजली बोर्ड के अन्दर कन्ज्यूमर वर्ग का एक सलाहकार प्रतिनिधि के रूप में बैठा हुआ है लेकिन एक बदकिस्मत वर्ग ऐसा भी है, जो संख्या में सब से अधिक कन्ज्यूमर कहलाता है लेकिन उस वर्ग का यानी किसान वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी बोर्ड के अन्दर आज तक नहीं है । सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया अगर किसान का प्रतिनिधि परामर्शदाता के रूप में बिजली बोर्ड में जाता है, तो इस सरकार का क्या नुकसान है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसको जाने दिया जाता जबकि दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं ? सरकार का इरादा किसानों की हमदर्दी का नहीं है । किसान के साथ ऐसे दुर्व्यवहार अनेक हो रहे हैं । मैं ऐसी सब बातें कहना चाहता हूं आप नाराज न हों । आपने ऐसी परम्परा जो बना दी है, वह बहुत बुरी है, बिना समझदारी की है और अकारण है । इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि बिजली बोर्ड में किसान वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए ।

सभापति जी उद्योगों का तो सरकार ध्यान रखती है लेकिन खेती का नहीं रखती क्योंकि वह बड़े लोगों का भला देखती है गरीबों का नहीं । बहुत बढ़िया सरकार है । सरकार गरीबों के लिए पहले हुआ करती है और अमीर के लिए बाद में । आप अमीर के लिए पहले हैं और गरीबों के लिए बाद में भी हैं अथवा नहीं ; इस का कई पता नहीं । यह हालत है सरकार की । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप इस तरीफ ध्यान दें । उद्योगों के अन्दर 2 पैसे यूनिट बिजली दी जारी है और उस के बाद सब्सीडी अलग से दी जाती है जिसकी मात्रा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है । लेकिन किसान से बीस पैसे से ले कर सत्ताईस पैसे यूनिट तक चार्ज किया जाता है अनुदान किसान के नाम पर किसान के नाम लिख दिया जाता हो तो पता नहीं उसे दिया तो नहीं जाता । मैं किसान के बारे में आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तो किसान की जमीन को नीलाम होने से रुकवा दें । दूसरे बिजली बोर्ड के अन्दर किसानों के प्रतिनिधि रखवा दें और पक्षपात बन्द करा दें । आप स्टेट के मुख्य मंत्रियों को इसका परामर्श भेजिये जिससे कि किसान की भी वहां सुनवाई होने लगे ।

16.30 hrs.

[Shri Chandrajit Yadav in the Chair]

दूसरी बात मैं सहकारिता के बारे में कहता हूं । सहकारिता किसान की सब से बड़ी समस्या है । सहकारिता को एक फर्जी जामा पहना रखा है । इसको जमने नहीं दिया जाता है । नेशनल आरगेनाइजेशन से ले कर नीचे गांव तक सभी सहकारी समितियों की हालत बिगाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं । गांव के लोगों का एक

[श्री कुम्भा राम आर्य]

सहकारी समिति के नाम और आकार के सम्बन्ध में दिमाग बनता है, उससे पहले उसका नाम बदल दिया जाता है, आकार बदल दिया जाता है। गांव के लोग कोशिश करके बदला नाम और आकार अपने दिमाग में बिठाते हैं इतने में तीसरा नाम और आकार स्थापित कर दिया जाता है। कभी उसका नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति, कभी ग्राम ऋणदात्री सहकारी समिति, कभी ग्राम समूह सहकारी समिति कर दिया जाता है। गांव का किसान इन सहकारी समितियों का नाम याद करने में ही आज तक उलझा हुआ है। अगर एक आदमी का नाम तीन-तीन, चार-चार बार बदल दिया जाए तो कैसे उसका नाम याद रह सकता है? गांव के अन्दर सहकारी समितियों की हालत बहुत खराब है। उससे बनने वाली मार्केटिंग सोसायटी को फेल करने के लिए सरकार ने अलग से खाद्य निगम कायम कर दिया। कायम इसलिये किया है कि स्टेट और नेशनल लेवल के सहकारी संघ फेल हो जाएं और स्टेट और नेशनल लेवल के सहकारी संघटनों के लिये आप चाहते हैं कि वे फेल हो जाएं। आप सारा का सारा पैसा निगमों को देते हैं सहकारी संस्थाओं को नहीं देते निगम बाजार में खड़े हो कर खरीद फरोख्त करते हैं, सहकारिता फिसक रही है। इसकी वजह यह है कि अगर सहकारिता के अन्दर सरकार का पैसा चला जाए, और इसको सरकार का समर्थन मिल जाए तो नौकरशाही क्या करे? नौकरशाही को बीच में से निकलना पसंद नहीं। हिन्दुस्तान की जनता इस नौकरशाही के रहते आजाद नहीं।

आज गांवों की हालत आपने क्या बना रखी है? एक गांव के अन्दर आपकी तीन-तीन, चार-चार सरकारें चलती हैं। इरीगेशन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग, एजूकेशन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग, हैल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग और कोआप्रेटिव का डिपार्टमेंट अलग है। इन महकमों के कर्मचारी एक दूसरे की मानपे नहीं और गांव वाले को अलग अलग डील करना पड़ता है। क्यों नहीं सरकार पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक यूनिट बना दे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यह बनाइये और उसका इंचार्ज सरपंच को बनाइये। गांव में सरपंच का हुक्म चलवाइये जिससे मालूम हो कि गुलामी चली गई और आजादी आ गई। आज सरपंच को सिचाई का पानी लेने के लिए ओवरसियर और बेलदार के पैर पकड़ने पड़ते हैं। राव साहब यह नौकरशाही का राज है इस नौकरशाही के चक्कर में आप और हम पिसे जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि गांव की ग्राम आप्रेटिव से ले कर दिल्ली तक की कोआप्रेटिव फेल हो रही है। इसको फेल करने के लिए निगम और भण्डारण की व्यवस्था अलग बना दी। सारा धन नौकरशाही के हवाले कर दिया। अब आप कहते हैं कि नौकर ज्यादा धन खर्च करते हैं, बेतरतीब का खर्च करते हैं। बनिया कम खर्च करता था। यह कहना था तो फिर उन्हें धन दिया ही क्यों। आपको कोआप्रेटिव को फैलाना चाहिए, सारा पैसा उसको देना चाहिए भण्डारण की मार्केटिंग की सारी व्यवस्था आपको कोआप्रेटिव के हवाले करनी चाहिए ताकि वहीं पैदा करने वाला हो वहीं खरीदने वाला हो। शिकियत का प्रश्न ही न रहे। लेकिन आज खरीदने वाला कोई, बेचने वाला कोई और पैदा करने वाला कोई नतीजा यह है कि सब जगह गड़बड़ घोटाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता को स्वतंत्रता दीजिये, स्वावलम्बी बनने का अवसर दीजिये। इसे नौकरशाही के शिकंजे से निकालने की मेहरबानी कीजिये, इससे आपके घर से कुछ लगेगा नहीं।

तीसरी बात मैं पंचायत राज की करना चाहता हूं। पंचायती राज आज हिन्दुस्तान में कहने मात्र को है। पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिये थे, वह अधिकर नहीं है। अधिकार तो दूर रह गये, अशोक मेहता ने जो रिपोर्ट दी थी कि पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण देने के लिये इसको संविधान में जगह देनी चाहिये, उस रिपोर्ट को लाल-फीते मे बांधकर अलमारी में रख दिया गया है। वह आज तक हमारे सामने नहीं लाई गई है। यह सब नौकरशाही की मेहरबानी है। नौकर नहीं चाहता कि देश की जनता उनके सामन सिर उठाकर चल सके। वह यह भी पसन्द नहीं करता कि गांव का गंवार आदमी एक कलक्टर को हुकम दे दे कि तुमको यह काम करना पड़ेगा।

मैं एक आश्चर्य की बात बताता हू अगर कोई जन प्रतिनिधि मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठ जाता है तो वह बड़े-से-बड़े अफसर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है, ट्रांस्फर कर सकता है, बर्खास्त करवा सकता है, लेकिन वह मुख्य मंत्री अगर चीफ मिनिस्टर की गद्दी से उतरकर गांव मे पंचायत की गद्दी पर बैठ जाये, सरपंच बन जाये तो वह पटवारी से रिपोट नहीं मंगवा सकता है। यह है पंचायती राज। जब वह मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठा था, बड़े दिमाग वाला आदमी था, चरित्र वाला आदमी था और सरपंच बनते ही उसका चरित्र हनन हो गया और बुद्धि भी खत्म हो गई। यह सब पंचायती राज के साथ मखौल है। आप इस नौकरशाही को पंचायत के हवाले कर दीजिये। पूरे गांव के सत्तर नौकर सरपंच के नीचे रहने चाहियें और जो तहसील के है वे प्रधान के नीचे रहने चाहिएं चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो, तभी पंचायती राज कायम होगा, इसके बगैर पंचायती राज कायम नहीं हो सकता। पंचायती राज कायम होने पर देश में तरक्की का काम शुरू होता, नहीं तो तरक्की का काम नहीं हो सकता है। अब तो करप्शन का काम होता है, मैं तेरी नहीं कहूंगा, तू मेरी न कहियो।

इस तरह से लोग बजट का पैमा ठिकाने लगा देंगे, आप कहेंगे कि हमने बहुत दिया और हम कहेंगे कि आपने कुछ नहीं दिया ? यह दोनों के लिये समस्या है ।

आप भी मंत्री महोदय, सदा यहां नही रहेंगे, कभी गांव में सरपंच बनना पड़ गया तो पटवारी आपको पसीना ला देगा । इसका प्रबन्ध अभी से कर लें । पटवारी को सरपंच के नीचे लगा दे । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यह गांव वालो के लिये बडा भारी संकट है, यह उनकी व्यथा कह रहा हू ।

श्री राम नगीना मिश्र (मलमपुर) : चौधरी साहब ने तो पटवारियों को समाप्त किया वह एक रुपया चार आने लेता था, लेकिन उन्होने नये लेखपाल पैदा कर दिये जो 10 रुपये लेते हैं

श्री कुंभाराम आर्य : मै यहा चौधरी साहब के हक मे बोल नही रहा हू, मैं तो किसान की व्यथा प्रकट कर रहा हू, इसमें कोई खराबी हो तो मुझे वापस दे दे ।

श्री राम नगीना मिश्र : मै तो यह कह रहा हूं कि यह चौधरी साहब ने किया था, जब वह सत्ता में थे

सभापति महोदय : ठीक है, वह व्यवस्था की आलोचना कर रहे है, किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की बात नही कह रहे है । चौधरी साहब अब आपने अपनी बात समाप्त कर ली ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): Sir, many hon members from the other side and also from my side have participated in the debate on the Budget Demands of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Rural Reconstruction My senior colleague, Shri Rao Birendra Singh, will later on wind up the debate. He will deal with most of the points that have been made in this debate with regard to agriculture and other important points. I am making this intervention mainly to deal with some of the points concerning Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Rural Reconstruction since I am handling these subjects.

At present, in the agricultural economy of India, crop husbandry plays a dominant role. It accounts for nearly 79 per cent of the value of total output in agricultural sector. The livestock sector accounts for 17 per cent and fisheries for nearly 1.7 per cent.

With this excessive dependence on crop husbandry, there is too much of instability in agricultural incomes from year to year. If agriculture is to be stabilised, we must develop the livestock sector as well as the fisheries sector in a big way. These sectors have a great deal of export potential. Moreover, these are sectors wherein small farmers, marginal farmers, agricultural labour and small fishermen can effectively participate.

In the above context, we propose to lay a much greater stress on livestock development and fisheries in the new Five Year Plan that is being formulated. In 1980-81 itself, a beginning has been made in this direction.

In order to meet the increased requirements of milk, our country needs to step up our milk production in a big way. Currently, our annual milk production is around 29 million tonnes. The intention is to increase this by about 8 million tonnes in the next five years. For this purpose, it is necessary to carry out a cross-breeding programme on a massive scale. Some beginnings have already been made towards introduction of a cross-breeding programme in the country. In 1980-81, we are intending to give it a big push forward For this purpose we have provided Rs. 5 crores in the Central Budget for the establishment of frozen semen stations in the different parts of the country for artificial insemination.

Along with cattle development, we intend to intensify our efforts in the dairy development. The main programme here is that of Operation Flood II, which will cover about 155 milk-shed districts. This massive project is intended to benefit 10 million families and cover about 15 million milch animals. As an indication of

[Shri R. V. Swaminathan]

our earnestness, I might add that the Plan outlay for cattle and dairy development which was about Rs. 51 crores in 1979-80 has been increased to Rs. 81 crores in the Central Budget now under consideration.

I think I should also take this opportunity to remove some misapprehensions regarding Operation Flood I. Far from being a failure, it has largely achieved the major objectives. Out of a sum of Rs. 112.60 crores generated from sale of gift SMP and butter oil, Rs. 106 crores have been utilised. The processing capacities of the 4 metropolitan dairies have been increased three-fold from 9 lakh litres per day to 27 lakh litres per day. In the 18 milkshed areas, feeder balancing capacities have been raised from under 7 lakh litres per day to 32 lakh litres per day. A substantial fleet of rail and road milk tankers capable of transporting nearly 30 lakh litres per day has been built up.

Nearly 1.2 million milk producers have been benefited through membership of 9,000 cooperative societies which provide facilities for technical inputs and veterinary care for their milch cattle. In those areas nearly 14 lakh artificial inseminations have been performed. For supplementary feeding of the animals, 8 cattle feed plants have been commissioned and 8 more are soon to be operational.

The result of these efforts has been that import of milk powder has declined from 48,000 tonnes in 1968-69 to 19,000 tonnes in 1979-80, while during the same period, the indigenous production increased from 20,000 tonnes to 64,000 tonnes.

Our studies have shown that in practically all the 18 milk sheds, about 70 per cent of the members of the societies are small or marginal farmers or landless labourers.

In our assessment the Operation Flood I approach has proved sufficiently successful to induce us to undertake the more ambitious Operation Flood II project which will now cover practically all the States.

Shri Digambhar Singh's point that step up of outlay on dairy will help only the urban consumers to get cheap milk and butter, is not correct. Firstly, around 35 per cent of the outlay will be clearly used for cattle development programmes in villages like provision of artificial insemination facilities, veterinary care, feed and fodder, semen banks, etc.

Secondly, the investments in processing capacities which would be around 35 per cent will also benefit the producers by providing them with an assured remunerative price and stable market and with access to the purchasing power of the urban consumers.

Thirdly, studies in the milksheds taken up under Operation Flood I have shown that the milk producers have secured at least 50 per cent increases in their cash incomes.

Finally, the processing capacities, particularly the feeder/balancing dairies are proposed to be owned by the producers cooperatives.

The hon. Member from Andaman said that Andaman should not be neglected. Any programme that the Government of India envisage, is meant for the whole of the country. Andaman is also a part of our country though it is situated at a far off place. We will not ignore it. He wanted that the programme of Operation Flood II should be introduced there. We are planning for it. Also cattle development covers Andaman & Nicobar Islands.

Poultry rearing is generally done by small and marginal farmers, tribals and other weaker sections of the community. There is growing demand for eggs and poultry meat. The present level of production of eggs, i.e., by 1979-80 is of the order of 12 thousand million eggs and 22 million broilers.

In order to meet the growing requirement of eggs and birds, we want to raise its production to 16,510 million eggs and 35 million broilers by 1984-85. This big step-up in poultry production will provide the much needed employment to rural people as well as increased production of eggs and birds to meet the national demand.

The indigenous hens lay about 60 to 100 eggs per year as against imported birds of improved variety which lay 220 to 260 eggs per year. The foreign countries supplied grand parent/parent stock to our country in which the male bird came from one particular line and the female from another particular line thus making it different to reproduce pure-lines as such.

The Indian farms thus had to remain dependent on foreign countries for replacement of birds at regular internals. It was also felt that adequate attention was not being paid by the private poultry breeders towards research and development for evolving new varieties of birds which could perform well under our agro-climatic conditions.

Keeping in view the danger of constant dependence on foreign countries for supply of breeding stock, Government have taken a policy decision to ban import of grand parent/parent stock from foreign countries. Government have also decided to encourage genuine poultry breeders in the country to take to basic breeding work (pure lines). This step will make the country self-reliant.

As I stated earlier, we need to give much greater attention to the development of fisheries. In this sector, we have a very big scope for inland fisheries development. In the Budget of 1980-81, we have provided Rs. 100 lakhs for inland fisheries development as against an amount of Rs. 15 lakhs provided in the previous year's Budget.

From the beginning of this year, a World Bank project for development of inland fisheries has been taken up in five States—Bihar, Orissa, West Bengal, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

It is proposed to get the village tanks etc., leased to individual fishermen or their co-operatives on a long-term basis. Efforts would be made to upgrade the ponds and the cultivation of fish in such ponds. Supply of fish seeds through Fish Seed Corporation is proposed to be arranged.

For development of inland fisheries, one of the ongoing schemes relates to fish farmers development agencies. About 93 such agencies already exist and are functioning. It is proposed to increase their number specially in the Northeastern States.

In regard to inland fisheries, one of the greatest bottlenecks is the inadequacy of fish seed. It is estimated that the overall requirement is nearly 6,000—million fish fry. The actual availability is hardly 1,000 million fish fry. We are making out the programme for development of large scale arrangement of fish seed production both in the public and the private sector.

In the sector of inland fisheries, one of the most promising areas is that of brackish water aquaculture. Brackish water fish farming has been tried successfully in West Bengal, Andhra Pradesh and Kerala. So far, pilot projects covering an area of 300 ha. have been taken up. It is proposed to ensure bigger projects for this purpose.

In the coming years, one of the most promising areas of development will relate to marine fisheries. As the hon. Members may be aware, only recently there has been a change in what is called the Law of the Sea. As a result of this change, India's jurisdiction stands extended by 200 miles from its coast.

[Shri R. V. Swaminathan]

This additional area is known as the Exclusive Economic Zone (EEZ). As a result of this, over 2.2 million square km. of oceanic area are now within the sovereign rights of our country. This offers us a new challenge and also a new opportunity.

For exploiting this new asset, we have to intensity our arrangements for survey of the fisheries resources, so that data become available to the fishery industry for exploitation. For this purpose, the Central Budget now under discussion provides Rs. 12 crores as against Rs. 7 crores provided last year.

For survey of deep sea fisheries resources, we are taking action to strengthen the exploratory fisheries project. Eight sophisticated vessels are already at the disposal of this project. Under the new Budget, we intend to increase the strength by another five vessels.

In order to help the fishing industry for locating good fishing grounds in different parts of the ocean, we propose to give periodically useful data either through bulletins or by radio broadcast about the available fishery resources in the deep sea areas.

For development of marine fisheries, one of the essential requirements is provision of fishing harbours. During 1980-81, a major fishing harbour at Paradeep is proposed to be taken up. In addition, 3 minor harbours at Chhinnamuttam (Tamil Nadu), Meenadakara (Kerala) and Astrang (Orissa) and about 10 landing sites will be taken up for consideration.

I am glad that we have completed the preparation of a Master Plan for fishing harbours throughout the country. We have circulated it to the State Governments for comments. During 1979-80, total expenditure on development of the fishing harbours was less than Rs. 3 crores. In 1980-81, we propose to more than double this amount.

One of the biggest constraints in the marine fisheries is the paucity of trained Skippers, Deckhands and Engineers. For this purpose, the training course in the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training is being revamped.

The trainees will now be given both institutional training and the required sea-service will also be arranged for them so that at the close of the training course they are qualified to appear in the competency examination. So far the trainees themselves had to arrange the sea-service with considerable difficulty.

It is hardly necessary for me to stress that deep sea fishing industries cannot be developed unless long-term loan or short-term loans are available for purchase of necessary vessels This responsibility was entrusted to the Shipping Development Fund Committee. During 1979-80, no loans were actually disbursed for a variety crores of loans would be disbursed.

During 1980-81, we propose to give special attention to this matter and sort out the problems. Our intention is that during 1980-81 about Rs. 6 crores of loans would be disbursed

During 1980-81, one of the aspects to which we propose to give pointed attention is that of policy governing the chartering of deep sea fishing vessels. We propose to streamline the policy keeping in view the short-term as well as long-term national interests. The intention would be to ensure that there is no over-exploitation of coastal fisheries.

We are also trying to see that no poaching takes place under the garb of chartered vessels. We will also try to see that the chartering policy facilitates collection of fisheries data and training of Indian personnel.

It is a matter of serious concern for all of us that in spite of nearly 30 years of planning and development,

there has not been any appreciable improvement in the lot of the rural poor. There is evidence to believe that economic disparities as well as regional imbalances have been aggravated.

The pursuit of the goal of higher GNP and the approach of general economic development has bypassed the rural poor. In fact, the realisation of the limitation of approach of general development and the conviction that the problem can only be tackled by a direct and frontal attack on poverty according to a programme launched by the then Congress Government under the leadership of Prime Minister Indira Gandhi led to the target group-oriented and area specific programmes like Small Farmer's Development Agency Programme, Drought Prone Area Programme, Desert Development Programme, etc.

17 hrs.

The eradication of poverty in the rural areas and the removal of regional imbalances, provision of employment, and bringing about a transformation of the rural sector are the specific responsibilities assigned to the Ministry of Rural Reconstruction. This Ministry seeks to achieve this objective through a number of programmes such as Small Farmers' Development Agency, Drought Prone Areas Programme/Desert Development Programme etc.

This Ministry intends to impart a new momentum to anti-poverty programmes, and to translate the Government's electoral commitments into reality as speedily as possible. In this context, the Small Farmers' Developmnt Agency and Integrated Rural Development Programmes have been virtually merged under one set of guidelines.

The main objective of the Small Farmers' Development Agency—Integrated Rural Development Programme is to launch a frontal attack on rural poverty through raising the incomes of the rural poor so as to enable them to go above the poverty line. The focus is on the family as a unit. These programmes are meant exclusively for the benefit of a target group consisting of small and marginal farmers, agricultural labourers, Harijans and Adivasis and rural artisans and craftsmen.

These programmes combine subsidies provided by Government and loans extended by banking institutions to finance investment activities which would raise the incomes of the beneficiary families substantially. Practically every viable economic activity in the rural areas is eligible for assistance under these programmes.

Agriculture, Animal Husbandry, Dairying, Poultry Farming and other ancillary occupations have a prominent role under these programmes. Rural industries and services are also particularly encouraged under these programmes.

Identified members of the target group are provided subsidies from Government funds. Small farmers are eligible for subsidy at the rate of 25 per cent of the cost of the scheme. Marginal farmers and agricultural labourers are provided subsidy at the rate of 33-1/3 per cent. An individual beneficiary may receive a maximum of Rs. 3,000 by way of subsidy. In the case of Scheduled Tribes, this ceiling is Rs. 5,000.

The Integrated Rural Development Programme is now under implementation in 2,900 blocks out of 5,004 blocks in the whole country. The provision under the Small Farmers' Development Agency — Integrated Rural Development Programme has been stepped up to Rs. 92 crores in the current year as against Rs. 85.92 crores in 1979-80.

Far from failing to provide adequate funds, the present Government is pumping in more resources for rural development.

The crucial question is not provisions in the budget; what is more im-

[Shri R. V. Swaminathan]

portant is the capacity of the State Governments and implementing agencies to utilise budget provisions effectively. In spite of several limiting factors, the State Governments and the implementing agencies have been able to utilise large parts of budget allocations and they have also been able to mobilise substantial credit support for this programme.

It is estimated that, on an average, one million families of the target group are being assisted in a year under this programme. At least one-fifth of these families belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The number of families assisted in a year is likely to be stepped up to 1.5 million.

The Government is most anxious to extend the benefits under this programme to the weaker sections in every part of the country. Accordingly, we propose to extend the Integrated Rural Development Programme to the whole of India as soon as possible with such modifications as may be necessary.

Once this programme is extended to every Block in the country and the administrative arrangements are streamlined, it would be possible for us to assist several million families belonging to the poorest sections of our population every year, and this will go a long way in mitigating poverty in the rural areas of India.

While implementing programmes for the benefit of families belonging to the target group, we are equally concerned about the development of specially backward and environmentally handicapped areas.

The major programmes for area development are the Drought Prone Areas Programme and the Desert Development Programme. The former is under implementation in 557 Blocks comprised in 74 districts. The primary objective of the programme is to upgrade ecological and production conditions in areas subject to repeated droughts.

The programme not only seeks to augment water resources, but it also seeks to promote improved dry land agricultural practices and create opportunities for non-crop incomes through subsidiary occupations in the animal husbandry sector.

A large afforestation and soil conservation programme has also been taken up under the programme. Some hon. Members have been critical of what they consider insufficient financial support to the programme. The cost of the programme is presently borne equally by the Union Government and the State Government concerned. The actual implementation of the programme is the responsibility of the State Government. The pace of expenditure has not always been satisfactory, with the result that it has not been possible for us to release the whole of the Central assistance.

We are in constant touch with the State Governments and are urging them to step up the expenditure so that a larger order of investment takes place in these resource-deficit areas.

Some hon. Members have referred to the need for expanding the coverage of the programme. This programme it may be appreciated, is in the nature of a pilot programme and is not meant to substitute the efforts of State Governments in the matter of improving productivity of land.

I may however, inform the House that a Task Force has been set up to go into this as well as other connected questions.

The Desert Development Programme is being implemented in 132 Blocks comprised in 20 districts. This programme has, broadly, the same objectives as the DPAP, but it lays greater emphasis on the control of desertification.

The hot deserts in Rajasthan, Haryana and Gujarat and the cold

deserts in the Ladakh region and Spiti are covered under the programme. The Task Force under reference is also going into the working of this programme.

Hon. Members are aware that efforts at re-designing the agrarian structure and at ensuring a more equitable distribution of land resources have been made through a variety of land reform measures.

It is true that these measures have not succeeded uniformly and that there are areas where implementation of the reform legislation has been unsatisfactory, but there can be no doubt that India's overall land reform performance has been outstanding by all standards.

Feudal institutions like Zamindari, Jagirdari etc. have been abolished and farmers in these areas have been brought into direct relation with the State. Tenants have become owners of land in several States and in every State, they enjoy protection against rack-renting and wilful eviction.

It has to be conceded that the benefits of progressive legislation have not accrued uniformly in all areas and that there is, in practice, considerable exploitation of tenants in utter violation of the provisions of the law. Fortunately, these areas are becoming fewer, largely because of the growing enlightenment among tenants.

The laws on land ceilings were revised extensively since 1972. An area of about 23.6 lakh acres has been taken possession of land an area of about 16 8 lakh landless persons.

A wholesome feature of the present land re-distribution policy is the clear advantage secured by landless persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The former account for about 40.6 per cent of all allottees; the corresponding share of Scheduled Tribes allottees is 12.5 per cent.

Government are aware that the pace of implementation of ceiling laws has not been as fast as they would have liked. The gap between the area declared surplus and taken possession of and between the latter area and the area actually distributed is quite large. We have drawn attention of State Governments to the need for greater expedition in disposal of land ceiling cases. We hope that tangible progress would be in evidence shortly.

Some hon. Members has observed that the flow of credit to the weaker sections has not been adequate. I am glad to inform the House that there has been significant improvement in the lending by cooperative as well as commercial banks to the weaker sections.

For example, the total short-term and medium loans advanced to small farmers by cooperative banks has gone up from Rs. 212.37 crores in 1973-74 to Rs. 488.80 crores in 1977-78, representing an increase from 27.8 per cent to 38.4 per cent of total landing for agriculture.

In the case of commercial banks, the total lending to small farmers has gone up from Rs. 118.81 crores (28.1 per cent) in 1973-74 to Rs. 457.46 crores (37.1 per cent) in 1977-78. At the end of March 1979, the coverage of small farmers formed 67.5 per cent of the total number of borrowal accounts for commercial banks.

The Government are conscious of the fact that the flow of credit to the weaker sections, including small farmers, marginal farmers, landless labourers and rural artisans, requires to be stepped up further.

With this end in view, several guidelines have been issued in the recent past covering aspects like timely sanction of loans, margin money security norms, lending procedure and simple loan application forms.

The Government have also advised that at least 50 per cent of the bank's total agricultural advances should go to small and marginal farmers by the end of 1982-83.

[Shri R. V. Swaminathan]

The Government have also announced in March 1980 the following measures to accelerate the flow of bank credit to the weaker sections:

(i) The target set in February 1977 of banks lending 33.3 per cent of their aggregate credit to the priority sector has been raised to 40 per cent to be achieved in the next five years.

A significant proportion within this overall target will be provided to the beneficiaries of the 20-Point programme which will be revitalised.

(ii) Banks will evolve special schemes tailored to the requirements of the beneficiaries of the 20-Point programme as part of their district credit plans.

(iii) The scheme of differential rate of interest and the programme of establishing regional rural banks will be pursued with greater vigour.

(iv) The Reserve Bank will evolve a monitoring system to evaluate the performance of different banks in the implementation of the 20-Point programme.

(v) Banks have been advised to adopt simplified application forms in regional languages and simplified lending procedures, including relaxed security and margin norms in their lending to agriculture.

The Khadi and Village Industries Commission now forms part of the Ministry of Rural Reconstruction. It is mainly through the village industries, within the Commission's purview that the programme of rural industrialisation is to be promoted.

Presently twenty-five village industries including Khadi are the main concern of the Khadi and Village Industries Commission. It is proposed to add another 15 village industries in their schedule.

The financial outlay for these programmes for the current year, as you already know, is Rs. 85.88 crores. The total production in the khadi and village industries sectors was worth Rs. 412.65 crores in 1979-80 which during the current year is expected to increase to Rs. 504.39 crores.

Similarly, the number of those employed in these sectors is proposed to be increased from the existing level of 29.45 lakhs to 33.79 lakhs by the end of the financial year. These figures include both full-time and part-time workers.

A conscious effort is being made to increase the number of full-time artisans/entrepreneurs. Also expansion of certain village industries namely, oil ghani, village leather, cottage match, non-edible oils and soap from processing and preservation fibre, poly vastra is proposed to be undertaken in order to generate opportunities for gainful employment in larger numbers.

The Food for Work programme has been in operation since 1977. It is being improved upon and refined in the light of certain defects and shortcomings noticed in its implementation by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission in their study of the programme concluded recently.

Apart from foodgrains, cash component has also been provided for the programme in order that the assets created thereunder are made durable. This considerably strengthened and rightly revamped programme will now be termed as the 'National Rural Employment Programme', as already reflected in the Budget.

The total cost of the programme is Rs. 340 crores which accounts for the cost of Rs. 20 lakh tonnes of foodgrains and Rs. 70 crores, as cash component.

Under this programme priority is being given to the projects of drinking water wells community construction sites, community irrigation wells, etc., for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Also, for the social forestry and afforestation programme, 10 per cent of the resources are proposed to be earmarked.

This programme has gained widespread popularity in the rural areas and assures the poorest two square meals a day. It has strengthened the rural infrastructure on a significant scale and to a considerable degree.

There is a proposal to provide employment opportunities to the educated unemployed belonging to rural families, living not necessarily below the poverty line.

It may be possible to impart technical skills necessary for the rural areas, and to provide the entire package of other required facilities to 50 educated youth, in this category, in every development block, per annum under this scheme. When this is done it would be possible to create the employment opportunities for all the segments of the rural society.

Sir, with these words, I conclude my speech. My senior colleague Shri Birendra Singh Rao will give elaborate reply to the debate.

SHRI L. S. TUR (Tarn Taran): Sir, I will speak in English I do not know why translator has not been provided for Punjabi, when for all other languages, translators have been provided.

Sir, Punjab contributes 60 per cent. of food in the Central pool. What is it that we get in return? I will say, nothing...

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): May I know, Sir, whether every Member is allowed to read his speech?

MR. CHAIRMAN: Mr. Daga, now that you have raised this point, I would like to say this. Normally it is not parliamentary practice to read a speech. I did not want to disturb the hon. Minister when he spoke for almost 40 minutes; it was almost totally written. I can understand if Members want to refer to facts or refer to certain written information etc. As we have given that concession to the Minister, if another Member wants that, we will allow him also.

SHRI L. S. TUR: Not to speak of Railways, Energy, Industry, Irrigation and other Departments of the Central Government, even the Agriculture Ministry treats Punjab partially. The ICAR spends about Rs. 100 crores annually but so far, no Institute or project has been opened in Punjab. It would have been better if the share of Punjab has been given to the Punjab Government or the Punjab Agricultural University. Every department which deals with State subject should earmark the share of the States as is being done in B&R Department so that the States can attend to these projects properly, instead of creating corporations. When Corporations are created they take the major share in ministerial expenses and the fund meant for the rural areas. And these corporations are misused by the Ministers. My only request is, there should be no misuse of the money to help the Minister and to help his *chamchas*. Sir, the IDA advanced loan to the farmers at the interest rate of 75 paise per 100 rupees. But the Central Government advanced loan to the farmers at the rate of 15 to 18 per cent. for agricultural purposes. It should have been advanced at 3 or 4 per cent rate, including the charges for middle agents who advance to the farmers.

Then, I would like to know why there is no insurance policy so far as crop is concerned. For every trade there is insurance cover and insurance policy can be taken. I do not know why crop and cattle are not included for this purpose of giving insurance cover. I do not know why crop and cattle are excluded in this respect. I think it should be possible for the Government to give insurance cover to the farmers so as to save him from losses due to flood, due to drought, and due to other calamities, and from

[Shri L. S. Tur]

loss of cattle, damage to crops and other things.

He cannot purchase cattle, he cannot purchase bullocks at the time the season starts. As there is insurance cover for all other trades, there should also be insurance facilities for agriculture so that the farmers are saved to some extent from natural calamities like floods, drought, etc.

17.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Sir, the price for the various agricultural crops should be fixed every year before the sowing season starts. Otherwise, if the crops are already sown, the farmer will be under suspense whether he would get proper price for his crops or not after the harvest. But in the case of every businessman he knows what will be the cost price and what will be the selling price I would request the hon. Minister to take up this matter with the Government and arrange to announce the prices of various crops before the sowing season starts, so that the farmer may decide what crop he should sow, which crop would be more remunerative etc

Sir, about 70 per cent of farmers are put to a lot of difficulties and there is no union for them to plead for them. The Government is also compelling them to form a Union for themselves so that their demands and grievances are ventilated through the Union. The Estimates Committee in their report of 1979, in Para 1.7 and 2.10 had pointed out the grave irregularities committed in ICAR. The Government has constituted UPSC for the selection of various both gazetted and non-gazetted personnel. But in so far as the ICAR is concerned recruitment of Scientists and other technical personnel are done by the Board constituted by the ICAR itself. Moreover it is a private body and the employees have no security of job. The ICAR is working in a partisan manner and there are many complaints about this organisation.

Sir, N.E.S. blocks were opened with great pomp and show. The States have been burdened with heavy ministerial expenses. No schemes have been included in the Plan for the farmers by the Central Government. The N.E.S. Block officers were entrusted with the important work which should be for the betterment of the agriculturists but now their duty is to distribute cement, diesel, etc. and no funds are provided to undertake the various schemes under the Plan. Various blocks were created in order to help the farmers and see that their leisure time during the off-season is gainfully utilised. There were proposals that small-scale industries were to be started in the villages and necessary staff were to be provided for this purpose. But so far no step has been taken to help the poor farmers. The farmers in Punjab are working very hard and they are producing more and more foodgrains for the country, but nothing has been done for them. They are under heavy debt because they are not getting the most remunerative prices for their produce. I would request the hon. Minister for Agriculture, Shri Birendra Singh Rao, kindly to look after the interests of the farmers who are suffering at the hands of others Agricultural implements, fertilisers and other articles of daily use should be made available to them at reasonable price. At present the prices of these articles have gone up. Prices for kharif crops should be announced keeping in view the prices of other articles used for agricultural purposes, so that the agriculturists could purchase those items. Crop insurance scheme must be implemented at the earliest.

(*The hon. Member then spoke a few sentences in Punjabi*)

श्री सतीश प्रसाद सिंह : (खगरिया) उपाध्यक्ष महोदय सब लोगों को यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय आय का सब से बड़ा श्रोत कृषि है

कृषि ही हम लोगों का सब से पुराना और प्रधान आय का स्रोत है । इंडस्ट्री या वाणिज्य से हमें जो आमदनी होती है, वह कृषि के मुकाबले कम होती है । हम लोग कृषि में तरक्की करते जा रहे है । हमारे कुछ साथी कहते है कि हमने तरक्की नही की है, लेकिन आकड़ों से पता चलता है कि पहली पंच-वर्षीय योजना में हमारी जो हालत थी, उससे दिन-प्रति दिन हमारी तरक्की होती गई है । हमारी पैदावार जो बढती गई और जो हमारे अनुसंधान करने वाले है उन्होंने भी मेहनत की, यहा के काश्तकारों ने भी मेहनत की । पहली पंचवर्षीय योजना मे 611 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था और हमे 692 लाख टन अनाज मिला । उसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे 850 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था और 920 लाख टन हम लोगो की उपज हुई । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोगो ने बजट को और बढाया और उस समय से अनाज मे वृद्धि होनी शुरू हुई । 1780 करोड रुपये का हम ने प्रावधान किया और 920 लाख टन अनाज हुआ । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे 3815 करोड रुपया हम लोगो ने बजट मे रखा और 1200 लाख टन अनाज मिला । फिर पाचवी पंचवर्षीय योजना में हम ने 8084 करोड़ रुपया लगाया, उस के बदले 1290 लाख टन उपज हम लोगो को मिला । इस ढग से हम देखते है कि हमारी कृषि में वृद्धि होती जा रही है और अब तो पोजीशन ऐसी हो गई है कि हमारा बफर स्टाक भी काफी है; साथ साथ हम ने इस देश से कुछ चावल और गेहू बाहर भी निर्यात किया है ।

लेकिन उसी के समकक्ष कुछ चीजो में हमें और तरक्की करनी है । जैसे दलहन और तिलहन में हम लोगों की उपज मे जो वृद्धि होनी चाहिए थी उस हिसाब से वृद्धि नही हो पाई है और हमें बाहर से इन चीजों को मंगाना पड़ता है जिन चीजों को पहले नही मंगाना पड़ता था। दाल की उपज के लिए और तिलहन को बढाने के लिए हमारे अनुसन्धान कर्ताओं को ध्यान देना चाहिए और ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि कम समय में हम उस चीज को अपने देश में इतना पैदा करें कि हमें दूसरे देशों से मंगाना न पड़े ।

जहां तक हमारे अनुसंधानकर्तागण हैं जैसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् है और ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इन की मदद से काफी अच्छे किस्म के बीज और अच्छे ढग से उस की शिक्षा का प्रचार करने की कोशिश की गई है । जहां ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उन के माध्यम से बहुत सारा काम हुआ है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अच्छे किस्म के बीज तैयार किए गए है । लेकिन उस का प्रचार जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नही हो पाया है । किसानों को जिस समय वह मिलना चाहिए उस समय नही मिल पाता है । इस वजह से जितनी तरक्की हमारी होनी चाहिए, जितनी पैदावार हमे बढ़ानी चाहिए उतना नही बढ सकते है ।

हमारी तरक्की तो हुई है लेकिन इस के साथ कुछ बात और ऐसी भी हुई है जो हमारे देश के लिए घातक है । जो छोटे किसान है, सीमान्त किसान हैं, लघु किसान है उन की तरक्की नही हो पायी है । उन की हालत दिन प्रति दिन बदतर हुई है यहा तक कि जो बहुत छोटे किसान हैं जैसे एक एकड या एक बीघा जमीन जिस के पास है उन की हालत यह हो गई है कि न तो वह खेती कर पाता है और खेती की जो लागत लगती है वह भी उस को नही मिलती है तो वह उस खेत को बेच कर शहर की तरफ जाना चाहता है। मजदूरी करना पसद करता है । एक एकड़ मे जो उस को मुनाफा होना चाहिए वह नही हो पाता है । इसलिए छोटे किसानों को इस बजट मे प्रावधान रहने के बादजूद भी अभी तक कोई फायदा नही हुआ है । इस बार इस बजट में 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । जो 1979–80 का बजट था उस तुलना में 41 परसेंट ज्यादा इस मे रखा गया है । और सब मुहकमो में 21 परसेंट ज्यादा रखा गया है लेकिन ऐग्रीकल्चर में 41 परसेंट ज्यादा वृद्धि की गई है । यह संतोषप्रद बात है और इस से जाहिर होता है कि सरकार का ध्यान ऐग्रीकल्चर की तरफ गया है और इसे ज्यादा बढ़ाना चाहती है । लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए कुछ बातो पर खास तौर से ध्यान देना होगा । छोटे किसान आज खेती से विमुख हो गए है, वे खेती करना पसन्द नही करते हैं । खेती छोड कर शहर की तरफ मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं । इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा । बीससूत्री

[श्री सतीश प्रसाद सिंह]

कार्यक्रम में बहुत सारे प्रावधान हैं लेकिन अगर उनका ठीक तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, अगर सही माने में छोटे किसानों तक उनका लाभ नहीं पहुंचा तो इस दिशा में सुधार होने की आशा बहुत कम है। इसलिए बीससूत्री कार्यक्रम का लाभ सही रूप में छोटे किसानों तक पहुंचना चाहिए। सरकार को यह बात सोचनी चाहिए कि छोटे किसान जिस ढंग से खेती करते हैं उसके अन्तर्गत उनको क्या लाभ पहुंचाए जा सकते हैं ताकि वे खेती से विमुख न हों, वे खेती में ज्यादा उपज पैदा कर उसके और मजदूरी करने के बजाए खेती करके अधिक लाभ कमा सकें।

सरकार बहुत ज्यादा पूंजी लगाकर खाद के कारखाने खोलती है लेकिन कुछ ऐसी मौलिक चीजें हमारे देश में हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान बहुत कम है। यदि उस तरफ समुचित ध्यान दिया जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि फर्टिलाइजर के बड़े कारखाने न खोले जायें, वे खोले जाये लेकिन किसानों को मुसीबत होती है कि सही मात्रा में कितनी खाद डालें जिससे जो उनका आउटपुट हो उसमें मुनाफा हो सके। मुनाफा न होने की वजह से उनमें असंतोष पैदा होता है और वे खेती से विमुख हो जाते हैं। मेरी राय में छोटे से छोटे किसान, जिसके यहां दो चार मवेशी होते हैं उसके गोबर के यूटिलाइजेशन के लिए गोबर गैस प्लान्ट्स लगाने की सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रकार से उसको गैस भी मिल सकती है जिससे वह ईंधन का काम ले सकता है। अभी उसको जो किरोसीन आयल या लकड़ी जलानी पड़ती है उसको भी रोका जा सकता है। वह गैस से अपना खाना बना सकता है और जो उसमें बाई-प्रोडक्ट होता है, खाद के रूप में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। उस खाद को डालने से भूमि में मायस्चर को रोकने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इस प्रकार जमीन भी सुधर जाती है जबकि केमिकल फर्टिलाइजर देने से वह लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी राय में हमारे टेक्नीशियन्स के द्वारा गोबर गैस के छोटे प्लान्ट तैयार किए जाने चाहिएं ताकि एक गरीब किसान जो दो मवेशी भी रखता है वह भी उसका इस्तेमाल कर सके। सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर ऐसे प्लान्ट्स पर 75 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, केवल 25 प्रतिशत ही किसान से लेना चाहिए। प्रत्येक किसान परिवार को ऐसे प्लान्ट मुहैया कराने चाहिएं ताकि हमारे किसानों की हालत सुधर सके। इसी प्रकार से ग्रीन मैन्योरिंग, जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी केमिकल खाद की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बिजली डिपार्टमेंट को यह हिदायत होनी चाहिए कि वे किसानों के साथ ज्यादती न करें। अभी जो बिजली के पम्प लगे हुए हैं वहां बिजली मिलती नहीं है लेकिन 5 हार्स पावर पर सौ रुपए मंथली वसूल कर लिया जाता है। पैसा न देने पर बिजली का सामान उठा लिया जाता है। इस ढंग से उन्हें तंग किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वहां पर एक मीटर लगा दें और जितनी बिजली कन्ज्यूम हो, उतना पैसा वह दे दें। इसमें काश्तकार को कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वे बिजली देते नहीं और बिजली उन्हें मिलती नहीं और उसके बाद बावजूद भी 100 रु० महीना उनसे टैक्स वसूल किया जाता है, इस प्रकार की परेशानी उनके साथ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कुछ बैंक खोले हैं, जिनसे लोगों को काफी लोन मिलता है और छोटे किसानों को भी मिलता है, लेकिन उसका इण्टरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, 11 से 13 प्रतिशत उनसे ब्याज लिया जाता है। उस लोन के बदले में उनको ऐसी मशीनें दे दी जाती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं और उसको ठीक करने के लिए एजेण्ट्स वहां पर बहाल कर दिए जाते हैं। जब वह एजेण्ट वहां से चला जाता है तो किसानों को परेशानी हो जाती है। डीजल ठीक नहीं मिलता है, डीजल खराब मिलने से बराबर मशीन खराब होती रहती है और उस मशीन के स्पेयर पार्ट्स

भी उनको नहीं मिलते हैं और मिलते भी हैं तो उन्हें एक रुपये की जगह छः रुपये देने पड़ते हैं। ऐसी हालत इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में पावर क्राइसिस है, बिजली की कमी है, तेल की कमी है, डीजल की कमी है, ऐसी हालत में जो साधन हम लोगों को मुहैया कर सकते हैं, वे हमें करना चाहिए। जैसे पहाड़ी एरिया में हम एयर-मिल बना कर बैठाते हैं, उसमें सब्सिडी देते है, जो किसान उससे पानी लिफ्ट कर सकता है, कुछ बिजली पैदा करके रोशनी भी जला सकता है और कुछ छोटे-छोटे उद्योग भी चला सकता है। इसलिए इस तरेफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बाते कह देना चाहता हू और वे यह है कि मेरा क्षेत्र दो प्रसिद्ध नदियों के बीच में है ---एक गगा नदी और दूसरी कोसी नदी। मेरा क्षेत्र कभी कोसी की बाढ से तबाह हो जाता है और कभी गगा की बाढ़ से तबाह हो जाता है। कभी गंगा जमीन को काट ले जाती है, कभी कोसी जमीन को काट ले जाती है। इसके लिए, मैंने इरिगिशन डिपार्टमेट को लिखा था कि उनके किनारो को मजबूत कीजिए। मेरे क्षेत्र की जमीन इतनी उर्वर जमीन है, इतनी अच्छी जमीन हे, यदि वहा सिर्फ पानी का इन्तजाम कर दिया जाए, जो पानी बर्बाद होता है, यदि उस पानी को काम में लाया जाए, तो मेरा क्षेत्र काफी अन्न पैदा कर सकता है। जिस ढग से पजाब कहता है कि मैं भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों को भी खिलाता हू।

मैं भी कहता हू कि यदि गंगा और कोसी की तराई एरिए में अगर पानी का इन्तजाम हो जाए, स्टेट ट्यूबवैल का इन्तजाम हो जाए, तो बिहार भी कह सकता है कि मैं भी भारत के बहुत बड़े हिस्से को अनाज दे सकता हू।

इन शब्दों के साथ इस बजट का मैं अनुमोदन करता हूं और उम्मीद करता हूं, मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान देंगे और रिसर्च में जो साइनटिस्ट लगे हुए हैं उन्हें आदेश देगे कि जो हमारे देश में कमी है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान दें। जिन चीजों के लिए यह देश नामी रहा है, जिसको देखकर अंग्रेज यहां आए थे और 300 वर्षों तक राज करके चले गए, उन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जो हमारे यहां मसाले पैदा होते हैं, उसकी कहां बिक्री होगी, कहां उसकी जरूरत है, किस देश में उसकी जरूरत है, उन मसालों की बिक्री के लिए उस देश में मार्केट खोजने का काम सरकार का है। किसान पैदा करता है, उसका सामान बिकता नही है। इसलिए इस ढंग का कोई कारपोरेशन बनाना चाहिए, कोई इन्तजाम करना चाहिए, ताकि उनके सामान को दूसरे देशों में सही मूल्य पर बेचा जा सके और उन्हे लाभ हो सके।

इन शब्दो के साथ मैं आपका बडा आभारी हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*SHRI GADADHAR SAHA (Birbhum): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we all know that in India agriculture is the main occupation of the people and in independent India the crisis in our agriculture is getting deeper every day. The number of the poor and those living below the poverty line is also increasing day by day. The imbalance in various States is also on the increase. The *per capita* availability of food is declining and production is falling. The high yielding variety programme has reached a point of stagnation even though the Central Government may think otherwise. As we find a stagnation in

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Gadadhar Saha]

agriculture, so also we see a recession in the industrial field. Every body has to bear the brunt of this situation. Therefore, Sir, in the interest of the masses I will suggest that there should be expansion of storage facilities and operation of crop insurance schemes immediately. There should be stabilisation of food prices as well as stabilisation of food supplies. There must be total elimination of middlemen who are exploiting the poor farmers in food crops as well as in commercial crops. The State should purchase directly from the producers. Speculative hoarding should also be totally eliminated. The poor farmers, bargadars, sharecroppers etc., in the rural areas should have easy access to institutional credit. Bank credit should be made easily available to them. The agricultural labourers should have assured employment throughout the year so that they may have a livelihood free from worry and anxiety. The Minimum Wages Act should be strictly enforced for the benefit of the poor labour keeping in view the rising prices and constant sliding down of their standard of living. Food and sugar cane commodities should be allocated to the States on the basis of their population and the actual demand. Other essential commodities should also be distributed on the same basis at the right price and in right time. The great regional disparity in wealth and income between man and man in various States and price disparities are growing. There were in 491 incidents of land disputes, 185 incidents of forcible harvesting, 191 instance of wage disputes, 191 cases of bonded labour and 107 instances of indebtedness.

Sir, it is necessary to bring about total restructuring of the existing agrarian structure which generates seeds of exploitation and which stands in the way of increase in production. It is necessary to completely overhaul the present land system.

The national Commission on Agriculture has given clear recommendations about the structure of agriculture and the reinstatement of farmers to tenanted land from which they were evicted and for the restoration of the rights of those farmers. There are many recommendations about agricultural policy also. The disparity in wealth and land holdings between man and man is to be abolished. As a new agricultural policy, it has been proved in other countries of the world also through research etc., that food production has to be increased for removing the regional disparities of income and wealth, for improving the standard of living of the masses, for removing poverty and for removing the regional imbalances in development; and that small size holdings are capable of increasing the food production than large size holdings, when this view has been accepted, at that time in India which is mainly an agricultural country, the Central Government through its programmes and policies brought about capitalism in our agriculture. New strategy and new technology was introduced in our agriculture. The Central Government chose to rely on that and thought that food production will go up and disparities will be removed. They wanted to hoodwink the people but they themselves very well know what they were doing. Their aim was that. This programme and policy created an awful situation. The same capitalistic system and elements of exploitation were re-established for whose abolition the zamindari system was once abolished. Zamindari system was abolished but in place of feudal landlords came the capitalist landords and in their hands bigger land holdings came to be concentrated. The lan holdings of poor farmers went in their clutches. Whatever good things were there in the tenancy legislation and land reform Acts etc. were not pursued and implemented vigorously by the centre, on the other hand there was provision of owners' right under the tenancy

of tenanted land', with the help of which the land owners took away control of land from the tenants and bargadars for personal cultivation but they whoodwinked the authorities and cultivated the land through hired labour. Therefore by this legislation there was large scale eviction, imbalance in land distribution and poverty increased. The tensions and conflicts which originate in the agraian society. the inherent powers of exploitation that generate them were rather given a boost. They gained strength and expanded. We can say without a trace of doubt that the factors of exploitation inherent in the old agrarian system which were sought to be removed, were actually strengthened by the new system and the Government depended more and more on the new class of capitalist and elite. It can be clearly said that this new policy has been implemented in the interest of big and rich land owners.

Sir, the banks were nationalised in 1969. What was outcome to that? The rich landowners were given huge financial assistance by these nationalised banks and as a result of that the rich farmers and landowners grew richer and richer. But the poor and marginal farmers and bargadars have to face infinite hurdles in getting loans from these banks even today. They don't get the minimum requirement of loans. This shows that the policy of the Government have actually helped a handful of rich farmers whereas a vast majority of poor farmers have been neglected. In this year's budget also we find that the same policy has been reflected. Government has withdrawn the income tax on agricultural property. We can very well see who are going to be benefited by that. It was a total surrender to this new class. Sir, democracy is really in danger.

In West Bengal at least an amendment has been effected in land legislation whereby the right of resumption of tenanted land by landowners has been restricted. Eviction of tenants has been made a cognizable offence. Resumption of land is now permissible only in the case of physical participation in agricultural operation, Hired labour is not allowed. The landowner will have to settle in the locality and the income from the land must be his principal source of income. Resumption of land from bargadars is not otherwise permissible now in West Bengal. Sir, even the provision of issue of receipts is not adhered to in many States and this is not insisted upon. But in West Bengal the non issuance of receipts also has been made a cognizable offence and the penalty is 6 months imprisonment and a fine of Rs. 1000. Because of implementation of land Reforms Act and this policy which protects the interests of the small farmers and bargadars, the West Bengal Government is being attacked time and again although it is functioning within the guidelines given by the National Commission on Agriculture and the Central Government. They are facing accusation after accusation for no valid reason.

I will like to say one more thing Sir. Production of food is in the interest of the masses. But the food policy of the Government and the mechanism adopted for transfer of surplus food over the minimum subsistence need of the farmer and the price at which such transfer takes place, these two agricultural Policy issues are highly politically controversial matters. All those big farmers who produce large quantities of food for commercial purposes are highly opposed to the procurement policy. Because of this opposition from big farmers, the dream of the Government of building up a formidable buffer stock of foodgrains has already been reduced to dust. The Central Government has completely surrendered to the big farmers' lobby all over the country in the interest of their political ambitions and for lack of political will. Government's sale also fluctuates around 10 per cent of total food consumption in our country.

Sir, the price at which the food grains and other commercial crops are procured from the farmes is very low and unremunerative. Whereas, the big farmers who control huge funds, purchase all these commodities at a cheap price, hoard them and sell them when the price rises. In this way they are able to make huge profits. The purchasing agencies of the Government like the Jute Corporation and other Corporations do not make direct purchase from the growers at the minimum procurement price fixed by Government. If the foodgrains and other commercial crops are purchased directly from the farmers by the State then the interest of the farmers can be protected.

Sir, the production of fish and development of fisheries has assumed great importance keeping in view the high price of fish. But the unit of Central Fisheries Corporation at Madras has been closed down and their unit at Howrah in West Bengal is also going to be closed down. This is very unfortunate. The hon. Minister has been requested for its revival. If this is not revived, then I would request that there should not be any retrenchment. The staff should be absorbed in other undertakings.

---

18 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Delay in Declaration of Results of Assembly Elections in Bihar.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Mr. Deputy-Speaker, Sir, due to certain circumstances over which we have no control, this discussion has, unfortunately, been delayed has been postponed twice. However, I am glad that this has come up now.

My purpose in bringing up this discussion is to try to highlight, in this House, certain happenings which have marred the recent Assembly elections in Bihar not because it is a question of rivalry between different parties—that is not the point I wish to emphasize at all—but something has happened which is quite unprecedented and out of all proportion to anything that has ever been seen before in the elections in this country. I think, it is a matter which should be of concern to all of us irrespective of all parties because, if what has happened is permitted to be repeated again, I am afraid this whole election system and the election machinery itself will break down.

In answer to Starred Question No. 340 which was asked on that day, the Minister laid a statement on the Table of the House in which, according to his own admission, in 81 constituencies in Bihar the declaration of results had to be held back for reasons he has stated in brief which are practically common in all the cases, that is, capturing of booths, snatching away of ballot papers, stamping in favour of a particular candidate, etc. These are all the reasons which the Minister himself has stated. Most of them are the same, booth capturing, snatching away of ballot boxes, ballot papers, destruction of ballot boxes, snatching away of ballot papers by persons armed with lethal weapons and so on.

In the Bihar Assembly, the total number of seats is 324. 81 constituencies were so affected that the results could not be announced for a period of upto 10 or 12 days after the polling was over. It means exactly, almost mathematically, 25 per cent, one-fourth of the total number of constituencies were affected, according to the Minister's statement. I do not know whether the statement is comprehensive or not. Similar things took place in so many other places also.